राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 14 नवम्बर 2025 वर्ष-8,अंक-257 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

दिल्ली ब्लास्टः एलएनजेपी अस्पताल में बिलाल ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या बढ़ी

नई दिल्ली लाल किला आतंकी हमले के बाद अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 35 वर्षीय बिलाल हसन ने बुधवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, बिलाल के फेफड़े और आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। वह सोमवार से वेंटिलेटर सपोर्ट पर था। अस्पताल में अभी भी 20 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सामने आया है कि लाल किला धमाके में शामिल 'सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल' ने विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपये नकद जुटाए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार, इस साजिश में शामिल चारों आरोपी डॉक्टर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और डॉ. उमर नबी ने संयुक्त रूप से यह धनराशि इकट्ठा की थी। पुलवामा निवासी और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. उमर नबी के जिम्मे यह रकम सौंपी गई थी। सोमवार शाम धमाके के वक्त वही हुंडई आई20 कार चला रहा था, जिसमें आईईडी लगाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच जारी गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मिलकर जांच कर रही हैं। जांचकर्ता समूह की वित्तीय गतिविधियों, संचार रिकॉर्ड और विश्वविद्यालयों से जुड़े संभावित संपर्कों की छानबीन कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को लेकर नाराज हुए रिटायर कर्मचारी

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) को मंजूरी दे दी है। यह एक तीन सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। बता दें कि करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) ने मुद्दा उठाया और इस लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आयोग में शामिल न किया जाना गलत है। वित्त मंत्री सीतरमण को लिखे पत्र में एआईडीईएफ ने कहा है कि जो लोग तीन दशक से ज्यादा लंबे समय से देश की सेवाकर चुके हैं, उन्हें 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) में शामिल न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यूनियन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का संदर्भ की शर्तें 7वें वेतन आयोग से अलग है। 7वें वेतन आयोग में पेंशन में संशोधन किए जाने का प्रावधान है, लेकिन 8वें वेतन आयोग से हटाया गया है। इसके बाद रिटायर हो चुके कर्मचारियों का नाराज होना लाजिमी है। हालांकि, फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। 8वां वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट बनाने में करीब 18 महीने का वक्त लगेगा।

छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की नई योजना

नईदिल्ली केंद्र सरकार छोटे और बंद पड़े हवाई अड्डों पर पुनः उड़ान शुरू करने के लिए नई योजना तैयार की है। केंद्र सरकार ने उन हवाई अड्डों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है।जहां ट्रैफिक नहीं होने के कारण एयरलाइन कंपनियां हवाई यात्रा शुरू करने के बाद बंद कर देती हैं। केंद्र सरकार अब ऐसे हवाई अड्डों और छोटे शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने पर एयरलाइंस कंपनियों को सब्सिडी देकर उनके घाटे को पूरा करेगी। 2016 से शुरू हुई इस योजना में अभी तक 649 नई एयर रूट जुड़ चुके हैं। 93 मार्ग पर उड़ाने शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए छोटे शहरों के हवाई अड्डों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों की हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए नए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देश के उन हिस्सों मे जहां पर्यटन और उद्योग के लिए हवाई यात्रा जरूरी है।स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे हवाई अड्डों से नियमित उड़ान शुरू हो। इसके प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए टिकट के दाम कम से कम हो, ताकि ट्रैफिक बढे। एयरलाइन कंपनियों को कम किराए के कारण जो नुकसान होगा। उसकी भरपाई केंद्र सरकार,एयरलाइन कंपनियों को करेगी।

बिहार में किसके के हाथ होगी सत्ता की चाबी, शुक्रवार को हो जाएगा साफ

सुबह 8 से होगी मतगणना शुरु, 38 जिलों में बने काउंटिंग सेंटर

पटना

बिहार की राजनीति में अब बस एक रात की दूरी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ आएगी। 38 जिलों में बने काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा का पहरा तीन-स्तरीय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बेचैनी उतनी ही बढ़ी हुई है। पहली बार बिहार में 67 फीसदी वोटिंग हुई है और इसमें महिलाओं ने पुरुषों से 9फीसदी ज्यादा मतदान कर इतिहास रच दिया।

विश्लेषकों का मानना है कि अगर एग्जिट पोल्स सही निकले, और एनडीए वाकई दोबारा सत्ता में लौटता है, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत यही महिला वोट बैंक होगा। परिस्थिति शांत दिख रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदान के अगले दिन ही चिंगारी डाल दी। उनका कहना है काउंटिंग को स्लो कराएं या फ्लैग मार्च कराएं हमारे लोग वोट चोरी रोकेंगे। चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ी, बेईमानी नहीं होने देंगे।

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि काउंटिंग स्लो कराने की साजिश है, पिछली बार भी खेल हुआ था, इस बार जनता चुप नहीं बैठेगी। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर जिले में स्ट्रॉन्ग रूम तैयार है, जिसकी चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। उम्मीदवारों के एजेंट्स को लाइव फीड दिखाई जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि छिपी न रह जाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काउंटिंग सेंटरों पर थ्री-टियर सिक्योरिटी सिस्टम लागू

है, पहली परत सीएपीएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की; दूसरी परत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की; और तीसरी परत जिला पुलिस की।

इसके अलावा मजिस्ट्रेट, एएसपी और डीएसपी स्तर के अफसर चौबीसों घंटे निगरानी में हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी रहेगी।

भारत और बोत्सवाना मिलकर विश्व व्यवस्था में देंगे सार्थक योगदानः राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबोरोन में बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और बोत्सवाना मिलकर एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ विश्व व्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के रूप में हमें अपने लोगों के सपनों और आकांक्षाओं, खासकर अपने युवाओं की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। वे ही भविष्य हैं और वे ही हमारे देशों की आगे की राह तय करेंगे। बोत्सवाना की राष्ट्र-निर्माण यात्रा में एक प्रारंभिक भागीदार होना भारत के लिए सम्मान की बात है। हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में फैला है- शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, व्यापार और निवेश। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी युवा जनसांख्यिकी और विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ, अफ्रीका वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे सकता है।

इस क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी गैबोरोन स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान बोत्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में बोत्सवाना के साथ अपनी साझेदारी को और अधिक गहरा करने तथा अपने विकास अनुभव को बोत्सवाना के साथ साझा करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। अफ्रीका भविष्य का महाद्वीप है।

अपनी युवा जनसांख्यिकी और विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ, यह महाद्वीप वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से बोत्सवाना के परिश्रमी लोगों और दूरदर्शी नेताओं ने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया है, जो शांति, स्थिरता और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सदैव तत्पर है। राष्ट्रपति मुर्मू छह दिवसीय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। चार दिवसीय अंगोला यात्रा के बाद अब वे बोत्सवाना के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीता भेजने पर सहमति जताने के लिए राष्ट्रपति बोको और बोत्सवाना के लोगों का धन्यवाद किया।

लद्दाख स्थित मुथ-न्योमा एयरबेस शुरू, वायुसेना प्रमुख सिंह ने किया उद्घाटन

इस संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय सेना की युद्ध तत्परता बढ़ने की उम्मीद

श्रीनगर

रणनीतिक दृष्टि से अहम लद्दाख स्थित मुथ-न्योमा एयरबेस का संचालन शुरू हो गया है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सी-130जे परिवहन विमान से वहां उतरकर एयरबेस का औपचारिक उद्घाटन किया। यह वायु सैनिक अड्डा करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और चीन के साथ एलएसी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अधिकारियों ने बताया कि वायु सैनिक अड्डे के चालू होने से संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय सेना की युद्ध तत्परता बढ़ने की उम्मीद है। एयर चीफ मार्शल सिंह के साथ पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा भी वायु सैनिक अड्डे पर मौजूद थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वायु सैनिक अड्डे को चालू करने के लिए 218 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। इस परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सितंबर 2023 में रखी गई थी।

सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर नतीजों का ऐलान आज

नई दिल्ली

देश के सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर मंगलवार (11 नवंबर) को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। अब 14 नवंबर (शुक्रवार) को इन चुनावों के नतीजे घोषित होने है। जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन, राजस्थान की अंता, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट शामिल हैं।

सीएम अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदेरबल दो सीटों से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया, इसके

बाद सीट पर अब उपचुनाव कराया गया है। वहीं, नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी।

राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव इसलिए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी नेता कंवर लाल मीणा को 2005 के एक पुराने मामले में दोषी ठहराने के बाद अयोग्य घोषित किया था। वहीं झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था। सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएएम) के उम्मीदवार सोमेश सोरेन, जो पूर्व विधायक सोरेन के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बीच सीधी टक्कर है। हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के बीच महामुकाबला है।

देश में रिसर्च को एक राष्ट्रीय जररुत के रुप में देखना चाहिएः नारायण मूर्ति

मुंबई

आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने भारत में साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और इनोवेटर्स के लिए मजबूत और अधिक सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि देश को रिसर्च एक लग्जरी की जगह एक राष्ट्रीय जरूरत के रूप में देखने की जरुरत है।

इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इंफोसिस पुरस्कार 2025 विनर्स को लेकर घोषणा कर मूर्ति ने कहा कि रिसर्च के लिए जिज्ञासा, इमेजिनेशन, हिम्मत और अनुशासन की जरूरत होती है इसलिए यह एक ह्युमन इंक्रायरी के उच्च आइडल को दर्शाती है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देकर याद दिलाया कि जो राष्ट्र बेसिक रिसर्च में गहनता से निवेश करता है वह साइंटिफिक प्रगति, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और सामाजिक कल्याण में सबसे आगे होता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को कोट कर कहा कि साइंस सिर्फ गरीबी, भुखमरी और अंधविश्वास सभी का समाधान बन सकती है। उन्होंने देश से एक बौद्धिक रूप से वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाए जाने की मांग की, जहां यंग रिसर्चर्स सीमित अवसरों जैसे बाधाओं से न जूझें और अपने काम को लेकर आगे बढ़ें। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने 15 मई को अपनी एज पॉलिसी को बदलकर प्राइज विनर्स के लिए

अप्पर लिमिट को 50 से घटाकर 40 वर्ष कर दिया था। हर एक इंफोसिस प्राइज में एक गोल्ड मेडल, एक प्रशस्ति पत्र और लाख डॉलर की राशि शामिल की गई है। 2025 प्राइज के साथ 6 रिसर्चर्स को मार्केट डिजाइन और अलोकेशन मैकेनिज्म, मैथेमैटिकल ऑप्टिमाइजेशन और ब्रेकथ्रू इन एल्गोरिद्म थ्योरी के एमपिरिकल एनालिसिस में में उनके योगदान को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया।

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा- इससे एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा, भारत की निर्यात क्षमता होगी मजबूत

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) देश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को नई ऊर्जा देगा और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, कि यह मिशन भारत के निर्यात ढांचे को परिणाम-उन्मुख, डिजिटल और प्रभावी प्रणाली की दिशा में ले जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है, जो न केवल भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाएगा बल्कि पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों, एमएसएमई सेक्टर और अधिक श्रम-प्रधान उद्योगों को भी सशक्त करेगा। यह पहल प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर एक ऐसा तंत्र तैयार करेगी, जो परिणाम आधारित और लचीला होगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए 'मेड इन इंडिया' की पहचान को विश्व बाजार में और मजबूती मिलेगी। यह कार्यक्रम एक कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल और डिजिटल-ड्रिवन फ्रेमवर्क पर आधारित होगा, जिससे वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 25,060 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी एमएसएमई और निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा, कि इस योजना से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार, सुचारू व्यावसायिक संचालन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) सदस्य क्रेडिट संस्थानों (एमएलआईएस) को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी

कवरेज प्रदान करेगी। इस योजना से पात्र निर्यातकों जिनमें एमएसएमई इकाइयां भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दोनों निर्णयों से भारत की आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ऋण के जाल में फंसे देशों से भारत के राज्यों को मिलती है सीख

प्रहलाद सबनानी

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं- जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)। ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को

व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था।

भारत में भी कुछ राज्य 'फ्रीबी' के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है।

सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार ये राज्य 'डेट ट्रैप' की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है।

संपादकीय

आतंकवाद के डाक्टर

परिस्थितिजन्य तफसील से यह स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली विस्फोट 'आतंकी हमला' ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सामान्य धमाके में साजिशकार नहीं होते। बुधवार को प्रधानमंत्री की ही अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। अक्सर यह युद्ध और आतंकी हमले के बाद ही बुलाई जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि होते हैं। युद्ध की स्थिति में तीनों सेना प्रमुखों को भी बुलाया जाता है। गृह सचिव और आईबी निदेशक भी बैठक में सम्मिलित होते हैं। दिल्ली विस्फोट की जांच 'राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी' (एनआईए) को सौंपी गई है, जिसे आतंकी हमलों की गहन जांच की विशेषज्ञता हासिल है। इस संदर्भ में फरीदाबाद की 'अलफलाह यूनिवर्सिटी' आतंकवाद के नए अड्डे के तौर पर उभरी है। फरीदाबाद के गांवों से जो 2900 किग्रा. विस्फोटक रसायन बरामद किया गया था, उसकी भूमिका भी साफ हो गई है। जो डॉ. उमर मुहम्मद कार-विस्फोट में मारा गया है, वह इसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वह जिस तरह मरा है, उसे हम एक नए किस्म का 'फिदायीन बॉम्बर' मान सकते हैं, क्योंकि उसकी कार में विस्फोटक था और उसी ने उसे सक्रिय किया होगा! जांच से बिल्कुल पारदर्शी स्पष्ट हो जाएगा। उमर कश्मीर के पुलवामा के कोइल गांव का निवासी था। विस्फोटक रसायन वाला आतंकी डॉ. मुजम्मिल शकील भी इसी गांव का रहने वाला था। वह इस आतंकी यूनिवर्सिटी में ही एसोसिएट प्रोफेसर था। तीसरा डॉ. सज्जाद अहमद भी पुलवामा का था। अलफलाह यूनिवर्सिटी में ही 45 वर्षीया डॉ. शाहीन सईद पदस्थ थी और एमबीबीएस, एमडी स्तर की फार्मकोलॉजी विशेषज्ञ थी। वह जैश-ए-मुहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया के नेतृत्व में आतंकी संगठन की महिला विंग 'जमात उल मोमिनात' की भारत में मुखिया थी। उसे संगठन में 'जेहादी औरतों' की भर्ती का जिम्मा दिया गया था। उसके भाई डॉ. परवेज को भी उप्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। 38 वर्षीय डॉ. आदिल कश्मीर के काजीकुंड का निवासी था और सहारनपुर, उप्र में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। यदि कश्मीर के नौगाम में जैश के धमकी वाले पोस्टर नहीं लगते, तो शायद आतंकवाद के 'डॉक्टर मॉड्यूल' का पदार्फाश न होता! इस गिरोह के 8 आतंकियों में 4 डॉक्टर कश्मीरी, 2 उप्र के हैं और दो मौलवी-इमाम शामिल हैं। सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उमर विस्फोट में भस्म हो चुका है।

चिंतन-मनन

सफलता का मार्ग

संग्रह की वृत्ति बहिमरुखता का लक्षण है। साधक क्षणजीवी होता है। अतीत की स्मृति और भविष्य की चिंता वह करता है जो आत्मस्थ नहीं होता। वर्तमान में जीना आत्मस्थता का प्रतीक है। एक साधक कल की जरूरत को ध्यान में रखकर संग्रह नहीं करता, पर एक व्यवसायी सात पीढ़ियों के लिए पूरी व्यवस्था जुटाने में संलग्न रहता है। यह बात सही है कि साधक अशरीरी नहीं होता, शरीर की अपेक्षाओं को वह गौण नहीं कर सकता; पर दैहिक अपेक्षाओं को लेकर वह मूढ़ नहीं हो सकता। उसका विवेक जागृत रहता है। वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखता है।

कभी-कभी साधक के जीवन में भी स्वच्छंदता, सुविधावाद और संग्रहवृत्ति जाग सकती है। प्रश्न उठता है कि इन वृत्तियों का उत्स क्या है? कौन-सी अभिप्रेरणा इन्हें उभरने का अवसर देती है? मेरे अभिमत से इन तीन संस्कारों का उद्भव तीन आकारों से होता है। वे तीन आकार हैं- अहं, अश्रम और असंतोष। स्वच्छंदता की मनोवृत्ति वहीं सक्रिय होती है, जहां अहंकार का नाग फन उठाए रखता है। अहंवादी व्यक्ति स्वयं को सब कुछ समझता है। उसे अपने सामने अन्य सभी लोग बौने दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में वह न तो किसी से मार्गदर्शन ले सकता है और न किसी के नियंत्रण में रह सकता है।

सुविधावाद का भाव वहां विकसित होता है जहां व्यक्ति श्रम से जी चुराता है, अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता और पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करता। अश्रम का बीज ही आगे जाकर सुविधावाद के रूप में पल्लवित होता है। इस दृष्टि से साधना के साथ श्रमशीलता की युति आवश्यक है। संग्रह वृत्ति का बीज है असंतोष। जिस व्यक्ति को पदार्थ में संतोष नहीं होता, वह संग्रह करने की बात सोचता है। जिस समय जैसा पदार्थ उपलब्ध होगा, उसी से आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी- यह विधायक चिंतन असंतोष की जड़ को काट सकता है और संग्रह की मनोवृत्ति को बदल सकता है। साधना की सफलता स्वच्छंदता, सुविधावाद और संग्रहवृत्ति में नहीं है।

श्वेता गोयल

बचपन के रंगों में रचा-बसा था नेहरू जी का जीवन दर्शन

जब प्रधानमंत्री बने बच्चों के खेल के साथी... भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत से भला कौन परिचित नहीं होगा। बच्चों से उन्हें इतना लगाव था कि उन्हें प्यार से 'बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू' कहा जाने लगा था। अपने कोट की जेब पर हमेशा प्रेम का प्रतीक गुलाब का फूल लगाए रहने वाले जवाहरलाल नेहरू बच्चों से इतना स्नेह करते थे कि आज भी वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री से पहले 'चाचा नेहरू' के रूप में ही अधिक याद किए जाते हैं। बच्चों के प्रति पंडित नेहरू के इस विशेष लगाव को देखते हुए ही सन् 1956 से उनके जन्मदिन को 'बाल दिवस' के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था और तभी से पंडित नेहरू का जन्मदिवस (14 नवंबर) बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जब उनके जन्मदिवस को 'बाल दिवस' के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, तब नेहरू जी ने कहा था, 'मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे देश के बच्चों ने मेरे जन्मदिन को ही 'अपना दिन' बना लिया है। इससे ज्यादा इज्जत और खुशी की बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मेरे मुल्क के बगीचे के इन कोमल फूलों और कोंपलों ने मुझे अपना इतना स्नेह दिया है। मेरी यही कामना है कि इन सबको फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिले।'

पं. जी के जीवनकाल के अनेक ऐसे संस्मरण एवं किस्से उद्धृत किए जा सकते हैं, जो उनकी महान शख्सियत और बच्चों के प्रति उनका अपार स्नेह बयान करते हैं। एक बार नेहरू जी बाल मंदिर देखने गए थे, जहां तीन से पांच साल तक के बच्चे पढ़ते थे। उस समय सभी बच्चे नाच-गाने में मग्न थे। जब पंडित जी वहां पहुंचे और दूर बैठकर बच्चों का नाच-गाना देखने लगे तो एक चार वर्षीया बालिका उनके पास आई और बड़े अनुरोधपूर्वक कहा कि आप भी हमारा साथ दीजिए। पहले तो पंडित जी काफी ना-नुकूर करते रहे। उन्होंने बच्चों को यह कहकर बहलाने का प्रयास भी किया कि इस बार तो नहीं लेकिन अगली बार तुम्हारे साथ जरूर नाचूंगा लेकिन जब उस बच्ची ने जिद पकड़ ली तो आखिर पंडित जी को उस छोटी सी बच्ची के आगे झुकना पड़ा और इतने विशाल देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उन बच्चों की खुशी के लिए उनके साथ वे बच्चा बनकर नाचे।

जब दीवाली का मौका होता तो वे अपने नाती राजीव और संजय के बाल मित्रों को आनंद भवन बुलाते और उनके साथ दीवाली मनाते हुए कहते कि बच्चों आतिशबाजी चलाकर दीपावली मनाओ और खुशियां बांटो। जो बच्चे पटाखे चलाते हुए डरते, उन्हें कहते कि जो बच्चे इन छोटे-छोटे पटाखों से ही डर जाएंगे, वे आगे चलकर देश के बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे? कभी-कभी वह इलाहाबाद में दीवाली की रात बाहर का नजारा देखने निकल पड़ते और रास्ते में गरीब बच्चों को भी मिठाईयां, नए कपड़े और पटाखे देते हुए उनके साथ पटाखे चलाने लगते।

एक बार उन्हें किसी जरूरी काम से दीवाली पर मास्को जाना पड़ा। उस समय तक वहां दीवाली के मौके पर पटाखे नहीं चलाए जाते थे लेकिन पंडित जी की दीवाली तो बच्चों के साथ पटाखे चलाए बिना अधूरी थी। इसलिए उन्होंने वहां भी बच्चों से पटाखे मंगवाए और काफी बच्चों को एकत्रित कर उनके साथ पटाखे चलाने लगे। वहां के बच्चे पटाखों की रंग-बिरंगी रोशनी और धूमधड़ाके से बहुत प्रभावित हुए और खुशी से झूम उठे। उसके बाद से मास्को में भी हर साल दीवाली के मौके पर पटाखे चलाने का दौर शुरू हो गया।

नेहरू जी छोटे थे, तब की एक घटना है। एक बार मैदान में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते-खेलते गेंद उछलकर लकड़ी के एक खोल में जा गिरी। खोल का मुंह छोटा था, इसलिए बच्चों से बहुत कोशिश के बाद भी गेंद नहीं निकल पा रही थी। जब नेहरू जी ने बच्चों की परेशानी को देखा तो उनसे रहा न गया। उन्होंने उन बच्चों से दो बाल्टी पानी मंगवाया और पानी लकड़ी के उस खोल में भर दिया। फिर क्या था, पानी भरते ही गेंद पानी में ऊपर आ गई और उन्होंने गेद निकालकर बच्चों को दे दी। सभी बच्चे बालक जवाहरलाल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए।

बच्चों के साथ-साथ देश और जनता से भी नेहरू जी बहुत प्यार करते थे और यही कारण था कि अधिकांश देशवासी भी उनसे उतना ही स्नेह करते थे और उन्हें आदर-सम्मान देते थे, जितना बच्चे देते थे। 74 वर्ष की आयु में 27 मई 1964 को पंडित जी स्वर्ग सिधार गए लेकिन अपने निधन से पूर्व अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा, 'मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां देश के उन खेतों में बिखेर दी जाएं, जहां भारत का किसान अपना पसीना बहाता है ताकि वे देश की मिट्टी में मिल जाएं।' ऐसे थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू!

(लेखिका डेढ़ दशक से अधिक समय से शिक्षण क्षेत्र में सक्रिय शिक्षाविद हैं)

साजिश :जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर कैसे बने आतंक के सौदागर?

मनोज कुमार अग्रवाल

लाल किला विस्फोट साजिश मामले में उच्च शिक्षित छह डॉक्टरों के नाम जुड़ जाने के बाद कई मिथक टूट रहे हैं जैसे अशिक्षा और बेरोजगारी आतंकवाद को जन्म देती है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस मामले में शिक्षित और लाखों मासिक की तनख्वाह पाने वाले सभी मुस्लिम दहशतगर्दी की साजिश से जुड़े मिले हैं। सवाल है कि इन्हें कौन रेडिक्क्लाइज (उग्र कट्टरपंथी) बना रहा है? जिंदगी देने वाले डॉक्टर ही दहशत फैलाने का औजार कैसे बन गए? ये कौन सी मजहबी तालीम है जो उच्च शिक्षित एम डी डॉक्टर्स का भी ब्रेनवॉश कर उन्हें दहशत फैलाने के नापाक मंसूबों से जोड़ देती है? पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग शहरों में आर्तकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटक सामग्रियों की बरामदी के बीच सोमवार शाम को लाल किले के पास जोरदार धमाका होना इस बात का प्रमाण है कि संभवत आर्तकियों ने इस घटना को बौखलाहट में अंजाम दिया है, लेकिन इसके साथ यह भी साबित होता है कि आतंकी देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़े जमा चुके है। आतंक का जाल पूरे देश में फैल चुका है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके में 12 लोगों की मौत और दो दर्जन से ज्यादा लोगों का घायल होना काफी दुःखद और हृदयविदारक घटना है, क्योंकि यह विस्फोट इतना भयानक था कि लोगों के चिथड़े उड़ गए। धमाके की वजह साफ नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस संबन्ध में कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आर्तकियों ने ही अपने नापाक मनसूबों को अंजाम दिया है।

संभवत दिल्ली में विस्फोट कर आतंकी पूरे देश में यह संदेश देना चाह रहे हैं कि तमाम गिरफ्तारियों के बीच उनका मनोबल गिरा नहीं है। दिल्ली, जो देश की प्रशासनिक और राजनीतिक धुरी है, में लाल किले जैसा ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक स्थान पर धमाका होना, सीधे-सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों को चुनौती है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां, फरीदाबाद और सहारनपुर में व्यापक छापेमारी चल रही थी और सात संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इसलिए यह मानना तर्कसंगत होगा कि यह धमाका आर्तकियों की बौखलाहट में की गई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसकी भयावहता इस बात में है कि यह दिखाता है कि नेटवर्क अब भी सक्रिय और संगठित है। आंकड़े और घटनास्थल की विस्तृत जानकारी ने यह संकेत दिया है कि यह कोई साधारण विस्फोट या हमला नहीं था, बल्कि लंबी परतों में फैला एक नेटवर्क चल रहा था। देश में विभिन्न स्थानों से कुल मिलाकर लगभग तीन टन के आसपास विस्फोटक पदार्थ और संबंधित सामग्री बरामद हुई है, और मामला एक व्हाइट कलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है यानी प्रोफेशनल्स, छात्र और नागरिक का भी शामिल होना समझ को झकझोर देता है। सबसे स्तब्ध करने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर संदेह हुआ उनमें मेडिकल डॉक्टर भी शामिल थे। रिपोर्ट बताती ताती हैं कि अनंतनाग के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से एके-47 राइफल बरामद की गई और दो-तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद यहीं से छानबीन आगे बढ़ी। जिन डॉक्टरों का नाम सामने आया है, उनमें अब जिन्हें हिरासत में लिया गया जिस कार में विस्फोट किया गया उसे भी एक डॉक्टर उम्र चला रहा था कुल छह डॉ के नाम सामने आ चुके हैं। इस से पता चल रहा है कि कैसे ईमानदार पेशेवर आड़ लेकर संवेदनशील स्थानों और सामाजिक विश्वास के ऊपर से भी आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। इससे पहले गुजरात से तीन आर्तकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आर्तकियों ने हमले की तैयारी के लिए अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों की रेकी की थी और आतंकी घटनाओं से इन्हें दहलाने की साजिश भी रची थी। आर्तकियों के मुताबिक अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाकों का नक्शा तैयार किया गया था। वहीं लखनऊ में आरएसएस के कार्यालय को भी निशाना बनाने के मंसूबे थे। दिल्ली में आर्तकियों की नजरें आजादपुर मंडी इलाके पर थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आतंकी राइसिन नामक जहर बना रहे थे जिससे हजारों लोगों को जान से मारने की तैयारी थी। पुलिस पूछताछ में एक अहम खुलासा यह भी हुआ था कि आतंकवादी आजाद शेख एक हफ्ते तक जम्मू-कश्मीर में रहा था, जहां पर उसने कुछ संवेदनशील इलाकों की जानकारियां भी जुटाई थीं। आर्तकियों ने हर जगह पर मौसम, शहरी बनावट और ट्रैफिक की पुख्ता जानकारी जुटाई थी। सभी आतंकी पाकिस्तान से संपर्क में थे और अपने आकाओं के इशारों पर काम कर रहे थे। पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर ही आर्तकियों ने भारत में बड़े नरसंहार की योजना रची थी। वह लोगों को राइसिन नाम का जहर देकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी अहमद सैयद कई दिनों से राइसीन पॉइजन इकट्ठा कर रहा था, ताकि मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। निःसंदेह यह दौर बहुआयामी चुनौतियों का है। एक ओर केंद्र तथा राज्य एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई और अंतर-एजेंसी समन्वय का जो नमूना हमें इन छापों से दिखा, वह सराहनीय है, सही सूचना-इंटेलिजेंस के भरोसे तेजी से छापे हुए गए और संभावित बड़े हादसों को रोका गया। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि हमारी जांच-विधान, संस्थागत निगरानी और पंजीकरण तंत्र में ऐसे षड्यंत्रों को पकड़ने-समेत रोकने के लिए और सुधार की जरूरत है। आज जिस तरह से आतंकवाद का चेहरा परिवर्तित हो रहा है, निःसंदेह वह भयभीत करने वाला है। लेकिन इससे कल होशियार होना भी आसान है, क्योंकि जब हमें पता चल गया है कि डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, छात्र संघ, कहीं-कहीं सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो हमें सिर्फ चिन्ता नहीं करनी, बल्कि सटीक कार्रवाई करनी होगी। आतंक को मात देने का समय अब है। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि आगे बढ़ना है, सामूहिक रूप से, सतर्क रूप से, अडिग रूप से। मगर इतना तय है कि लाल किले के पास धमाका कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक तरह से देश पर हमला है। यह हम सबको यह याद दिलाता है कि आतंक का जाल अब हमारी गलियों, विश्वविद्यालयों, डिजिटल चैट ग्रुपों और वित्तीय तंत्रों में घुस चुका है। अब यह युद्ध सिर्फ सैनिकों या पुलिस का नहीं, बल्कि नागरिक समाज, तकनीकी संस्थानों, शिक्षकों, और नीति निमार्ताओं सहित हम सबका है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास, शिक्षा, न्याय और एकता से सुनिश्चित की जाए। आतंकवाद को हराने का अर्थ सिर्फ आर्तकियों को मारना नहीं, बल्कि उस मानसिकता को खत्म करना है जो उन्हें जन्म देती है। इसके लिए सबसे पहले खुफिया एजेंसियों को देश में फैले आतंक के जाल को तोड़ना होगा और यह काम सभी केंद्र और राज्य एजेंसियों को मिलकर करना होगा। यह काम आम नागरिकों के सहयोग के लिए बिना संभव नहीं है। देश के राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि इस विषय पर राजनीति नहीं करते हुए सरकार का साथ दें। आतंकवाद पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं हो। हकिकत यह है कि भारत का हर नागरिक, सुरक्षा संस्था और राज्य प्रशासन मिलकर इस खतरे को तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम इसके स्त्रोत, नेटवर्क, लॉजिक और सहयोगियों तक पहुंच नहीं पाते। हमें एक रणनीति के साथ काम करना होगा, जहां आतंक सिर्फ दवाया नहीं जाए, बल्कि जड़ से उखाड़ दिया जाए। सभी के सहयोग से ही देश में फैले आतंक के जाल को तोड़ा जा सकता है लेकिन उच्च शिक्षित डाक्टरों का आतंकी तंजीम से जुड़न बेहद चौकाने वाला और गहन चिंता का विषय है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

डीएचएल समूह भारत में करेगा 1 अरब यूरो का निवेश

मुंबई वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीएचएल समूह ने 2030 तक भारत में करीब 1 अरब यूरो निवेश करने की घोषणा की है। यह कदम कंपनी की रणनीति 2030- त्वरित सतत विकास योजना का हिस्सा है और भारत को एक प्रमुख विकास बाजार के रूप में दर्शाता है। डीएचएल का लक्ष्य भारत में अपने ग्राहकों के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स सेवाओं का विस्तार करना है। कंपनी का यह बहु-स्तरीय निवेश कार्यक्रम जीव विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा, नई ऊर्जा, ई-कॉमर्स और डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित होगा।

महिंद्रा और मनुलाइफ ने भारत में जीवन बीमा संयुक्त उद्यम की घोषणा की

शुरुआती पांच वर्षों में प्रत्येक शेयरधारक 1,250 करोड़ का निवेश करेगा

नई दिल्ली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गुरुवार को कनाडा की जीवन बीमा कंपनी मनुलाइफ के साथ 50:50 अनुपात में जीवन बीमा संयुक्त उद्यम स्थापित करने की घोषणा की। दोनों साझेदारों की ओर से इस नए उद्यम में 3,600-3,600 करोड़ रुपये का निवेश होगा। शुरुआती पांच वर्षों में प्रत्येक शेयरधारक 1,250 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। कुल पूंजी प्रतिबद्धता दोनों कंपनियों के लिए 7,200 करोड़ रुपये तक है। यह संयुक्त उद्यम महिंद्रा और मनुलाइफ की भारत में मौजूदा उपस्थिति को मजबूत करेगा और देश के तेजी से बढ़ते जीवन बीमा बाजार में ग्राहकों की वित्तीय भलाई बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। महिंद्रा समूह की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गहरी वितरण क्षमताएं और निष्पादन उत्कृष्टता इस विस्तार को सफल बनाने में मदद करेंगी। महिंद्रा समूह के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि जीवन बीमा व्यवसाय में यह कदम वित्तीय सेवा क्षेत्र के व्यापक विस्तार की दिशा में तार्किक है। यह संयुक्त उद्यम दोनों कंपनियों के लिए भारत में जीवन बीमा क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी बाजारों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है।

प्रेस्टीज एस्टेट्स का मुनाफा 95 फीसदी बढ़कर 457.4 करोड़ हुआ

कंपनी की कुल आय में 11 फीसदी की वृद्धि

नई दिल्ली प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जुलाई-सितंबर तिमाही में शानदार वित्तीय परिणाम दर्ज किए। कंपनी का मुनाफा 457.4 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 234.6 करोड़ रुपये था। यह करीब 95 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 2,697.8 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 2,423.8 करोड़ रुपये थी, यानी लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि। प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही विशेष रूप से उत्साहजनक रही। मजबूत बिक्री गति और बढ़िया नकदी प्रवाह ने ग्राहकों और निवेशकों के बीच कंपनी के ब्रांड में विश्वास बनाए रखा। चेयरमैन ने कहा कि कंपनी का फोकस समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने, पूंजी का विवेकपूर्ण आवंटन करने और प्रमुख विकासशील बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर रहेगा। देश के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर में से एक प्रेस्टीज ग्रुप लगातार स्थिर और मजबूत प्रदर्शन के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया

सरकार ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी दरें तय की

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली धमाके की निंदा के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य निर्णय के तहत कैबिनेट ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरें तर्कसंगत बनाने को मंजूरी दी। यह कदम क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंतर्गत लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी दरें तय कर दी हैं। कैबिनेट ने यह फैसला क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत लिया है। इस फैसले से इन खनिजों के ब्लॉक की नीलामी तेज होने की संभावना है। इससे लिथियम, टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और नाइओबियम जैसे दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों का भी फायदा होगा। संशोधित रॉयल्टी दरों के अनुसार, सीजियम और रुबिडियम, प्रत्येक पर उत्पादित अयस्क में निहित संबंधित धातु के औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) के आधार पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी लगेगी।

कैबिनेट के अनुसार जिरकोनियम पर एएसपी की 1 प्रतिशत रॉयल्टी दर होगी, जबकि ग्रेफाइट पर 80 प्रतिशत या उससे अधिक स्थिर कार्बन वाले अयस्क के लिए एएसपी का 2 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से कम स्थिर कार्बन वाले अयस्क के लिए 4 प्रतिशत रॉयल्टी दर लागू होगी। दरअसल, सरकार का मानना है कि ग्रेफाइट पर एड वेरोरम (बाजार मूल्य के अनुसार) रॉयल्टी तय करने से अलग-अलग ग्रेड के ग्रेफाइट के मार्केट रेट के हिसाब से रॉयल्टी कनेक्शन होगा। इससे घरेलू उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही आयात पर निर्भरता भी कम होगी। सप्लाई चेन की परेशानियां भी घटेंगी और नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

रिन्यू करेगी आंध्र प्रदेश में 82,000 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश

अमरावती आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को कहा कि कार्बन मुक्त समाधान पेश करने वाली कंपनी रिन्यू राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में 82,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। आईटी मंत्री ने बताया कि यह निवेश सोलर इंजन और वेफर निर्माण, परियोजना विकास, हरित हाइड्रोजन और अणु प्रौद्योगिकी जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में होगा। 16 मई को अनंतपुर जिले में रिन्यू ने 22,000 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसमें 4.8 गीगावाट क्षमता का हाइब्रिड फार्म और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। मंत्री ने कहा कि पांच साल बाद राज्य लौटकर यह घोषणा करना गर्व की बात है कि रिन्यू पूरी नवीकरणीय ऊर्जा श्रृंखला में निवेश कर रही है।

सेबी में हितों के टकराव और खुलासे के नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित

नई घोषणा : सभी वरिष्ठ अधिकारियों को करना होगा पूर्ण खुलासा

नई दिल्ली भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में हितों के टकराव और खुलासे (के नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सेबी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी सभी संपत्तियों, देनदारियों, ट्रेडिंग गतिविधियों और संबंधित पक्षों के साथ संबंधों की घोषणा कई चरणों में करनी होगी- नियुक्ति, सालाना, प्रमुख घटनाओं और पद छोड़ने के समय। समिति ने सुझाव दिया कि बोर्ड या वरिष्ठ पदों के आवेदकों को किसी भी वास्तविक, संभावित या अनुमानित हितों के टकराव का खुलासा करना अनिवार्य होगा, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय मामलों दोनों शामिल हैं। इसके अलावा 'परिवार' की परिभाषा को व्यापक बनाया जाएगा। इसमें पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, कानूनी अभिभाव्य के तहत आने वाले व्यक्ति और अन्य आर्थिक रूप से आश्रित रिश्तेदार शामिल होंगे। समिति ने वरिष्ठ अधिकारियों के नए निवेशों को पेशेवर रूप से प्रबंधित पूल्ड योजनाओं तक सीमित करने और व्यक्तिगत पोर्टफोलियो का 25 फीसदी तक ही निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया। यह प्रतिबंध उनके जीवनसाथी और आर्थिक रूप से आश्रित परिवार पर भी लागू होगा। अंशकालिक सदस्यों को इस निवेश सीमा से छूट दी जा सकती है, लेकिन वे अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी पर ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा ने की, जबकि उपाध्यक्ष थे इंजेती श्रीनिवास। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने मार्च 2025 में समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य सेबी में पारदर्शिता बढ़ाना, हितों के टकराव के प्रबंधन को मजबूत करना और लोगों का भरोसा कायम करना है।

शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद

मुंबई

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मुनाफावसूली हावी होने से हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच ही बाजार पर दबाव पड़ा जिससे बाजार ऊपर नहीं आ पाया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरो वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 12.16 अंकों की हल्की बढ़त के साथ ही 84,478.67 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 3.35 अंक की हल्की तेजी के साथ 25,879.15 पर बंद हुआ। दिन के दौरान बैंकिंग शेयरों में तेजी रही को और निफ्टी बैंक ने नया ऑल-टाइम हाई 58,615.95 बनाया। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई और यह 107.30 अंक करीब 0.18 फीसदी की मजबूती के साथ 58,381.95 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एचसीएल टेक के शेयरों को लाभ हुआ जबकि जोमैटो, एमएंडएम, टाटा स्टील, बीईएल, टीसीएस, एचयूएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एसबीआई के शेयर गिरे। आज लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में कमजोरी

रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 210.25 अंक या 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 60,692.05 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 66.80 अंक या 0.37 फीसदी की कमजोरी के साथ 18,183.65 पर था।

इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच ही को बाजार हल्की बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स शुरुआती सत्र में 84,525.89 अंक पर खुला, लेकिन जल्दी ही लाल निशान में चला गया। सुबह शुरुआत के बाद यह 98.19 अंक की गिरावट के साथ 84,368.32 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी भी मजबूत शुरुआत के बाद गिरावट में आ गया और 13.45 अंक फिसलकर 25,862.35 पर कारोबार करता दिखा। वहीं वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिश्रित रुख देखने को मिला।

जापान का निक्केई 225 0.4 फीसदी बढ़ा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3 फीसदी ऊपर रहा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.2 फीसदी गिरा। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स 0.68 फीसदी चढ़ा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.26 फीसदी गिरा और एसएंडपी 500 लगभग सपाट बंद हुआ।

एनटीपीसी कोयला गैसीकरण और परमाणु ऊर्जा में करेगी प्रवेश

अगले 3-4 साल में हर साल 50-100 लाख टन सिंथेटिक गैस का उत्पादन करने की योजना

नई दिल्ली

सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अगले 3-4 साल में हर साल 50-100 लाख टन सिंथेटिक गैस का उत्पादन करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि गैस उत्पादन की लागत लगभग 10-12 डॉलर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी। अधिकारी ने कहा कि गैस की कीमत वर्तमान में मिलने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आसपास रखी जाएगी और खरीदार तलाशने में कोई समस्या नहीं होगी। एनटीपीसी उत्पादन के लिए अपने कोयले का उपयोग करेगी और उत्पादित गैस या तो घरेलू बाजार में बेची जाएगी या कंपनी के अपने संयंत्रों में उपयोग होगी। कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए कंपनी प्रौद्योगिकी सलाहकार लाने पर भी विचार कर रही है, और इस वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए निविदाएं जारी करने की योजना है। सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक 10 करोड़ टन गैसीकरण का लक्ष्य तय किया है और 8,500 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया है।

इस पहल से प्राकृतिक गैस का देश के ऊर्जा मिश्रण में हिस्सा वर्तमान 6त्न से बढ़ाकर 2030 तक 15 फीसदी करने का लक्ष्य पूरा होगा। एनटीपीसी ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी कदम रखा है।

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें घोषित

चंडीगढ़ सबसे सस्ता शहर, पेट्रोल 94.30 और डीजल 82.45 रुपए प्रति लीटर

नई दिल्ली राष्ट्रीय तेल कंपनियों (ओएमसी) ने गुरुवार को सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी किए। इन कीमतों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपये-डॉलर का विनिमय दर, एक्साइज ड्यूटी, डीलर

कमीशन और राज्यों के वैट के आधार पर किया जाता है। चूंकि हर राज्य का वैट अलग होता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम भी राज्यों में भिन्न होते हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपए और डीजल 92.15 रुपए प्रति लीटर जबकि हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपए और डीजल 95.70 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपए और डीजल 92.34 रुपए, बेंगलुरु में पेट्रोल 02.92 और डीजल 89.02, और कोलकाता में पेट्रोल 103.94 और डीजल 90.76 प्रति लीटर दर्ज किया गया। चंडीगढ़ सबसे सस्ता शहर रहा, जहां पेट्रोल 94.30 और डीजल 82.45 रुपए प्रति लीटर है।

भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7 फीसदी बढ़ेगी: रेटिंग एजेंसी

2026 और 2027 में भारत की वृद्धि लगभग 6.5 फीसदी रहने का अनुमान

नई दिल्ली

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने गुरुवार को अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 फीसदी बढ़ने का अनुमान लगाया है। 2024 में यह दर 6.7 फीसदी थी। एजेंसी का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत बुनियादी ढांचे पर खर्च और ठोस घरेलू उपभोग से समर्थन मिल रहा है। हालांकि निजी क्षेत्र अभी पूंजीगत व्यय को लेकर सतर्क है। 2026 और 2027 में भारत की वृद्धि लगभग 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है। अमेरिका में कुछ भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी शुल्क के बावजूद निर्यातकों ने अन्य बाजारों में निर्यात बढ़ाने में सफलता हासिल की है। सितंबर में कुल निर्यात 6.75 फीसदी बढ़ा, जबकि अमेरिका को निर्यात में 11.9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। मूडीज ने कहा कि निर्यात और घरेलू बाजार का विविधीकरण भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि में मदद करेगा। एजेंसी ने यह भी कहा कि कम मुद्रास्फीति के बीच मौद्रिक नीति तटस्थ से उदार बने रहने की संभावना है। इससे आर्थिक वृद्धि को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। मूडीज के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था

2025 में 5 फीसदी बढ़ेगी, लेकिन 2027 तक यह वृद्धि धीरे-धीरे 4.2 फीसदी तक घट सकती है। वैश्विक जीडीपी की वृद्धि दर 2025 में 2.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जो 2024 की 2.9 फीसदी दर से कम है। 2026 और 2027 में यह क्रमशः 2.5 फीसदी और 2.6: फीसदी रहने की संभावना है।

निर्यातकों को राहत, कैबिनेट से 45,060 करोड़ की दो योजनाएं मंजूर

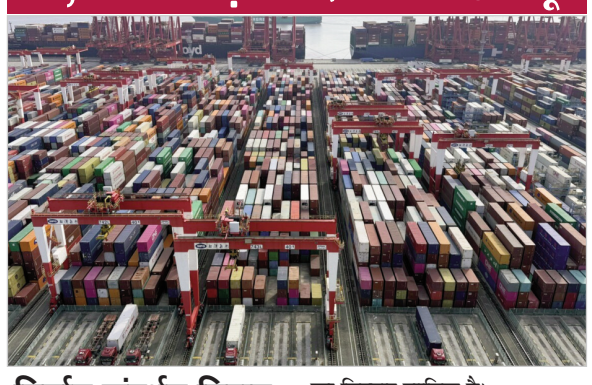

निर्यात संवर्धन मिशन और ऋण गारंटी योजना से एमएसएमई को मिली मजबूती

नई दिल्ली

अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे निर्यातकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुल 45,060 करोड़ रुपये की दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य भारतीय निर्यात क्षेत्र को सहायता, सुरक्षा और नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करना है।

इन योजनाओं में 25,060 करोड़ रुपये का निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) और 20,000 करोड़ रुपये की निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) का विस्तार शामिल है।

यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों की हालिया बैठक के एक सप्ताह बाद की गई, जिनमें अमेरिकी शुल्क से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र शामिल थे। निर्यात संवर्धन मिशन वित्त वर्ष 2031 तक लागू रहेगा और इसका मकसद भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

यह दो उप-योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से लागू किया जाएगा। इनके तहत ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, नए बाजारों में विस्तार हेतु ऋण सहायता और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ दी जाएंगी।वहीं ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) के विस्तार से एमएसएमई निर्यातकों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सस्ते ऋण तक आसान पहुंच प्राप्त होगी।

फिर तेजी से भाग सकता हैं सोना, संस्थागत और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी

मुंबई

सोना फिर दुनिया भर के निवेशकों का पसंदीदा सुरक्षित निवेश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, सोना अभी भी मजबूत स्थिति में है और इसकी कीमत 4,368 से लेकर 4,600 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक जाने की उम्मीद है, जबकि नीचे 3,890 और 3,510 डॉलर पर सपोर्ट रहेगा। अक्टूबर में सोने की कीमत 4,368 डॉलर तक पहुंची थी, इसके बाद यह महीने के अंत तक थोड़ा गिरकर 4,000 डॉलर के नीचे आ गई। यह गिरावट पिछले एक महीने में अमेरिकी डॉलर के 1.4 प्रतिशत मज़बूत होने की वजह से हुई। लेकिन जानकारों का मानना है कि लंबे समय में सोने का रुझान अब भी ऊपर की ओर है, क्योंकि संस्थागत और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी लगातार बनी हुई है, और डॉलर पिछले एक साल में कमजोर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से लोग अपना पैसा सुरक्षित जगह, यानी सोने में लगा रहे हैं। इसके अलावा, पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 8 प्रतिशत तक गिर गई है, जिससे सोना और दूसरी चीजें (कमोडिटीज) महंगी हो गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अब तक सोने से जुड़े फंड्स में लगभग 65 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। इनमें से 20 अरब डॉलर सिर्फ पिछले तीन महीनों में लगाए गए हैं। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अब अपने विदेशी भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी कम करके सोना खरीद रहे हैं, ताकि आर्थिक अनिश्चितता से बच सके। रिपोर्ट कहती है कि यह एक नया निवेश रुझान है, जहां देश और बड़े संस्थान अब अमेरिकी बॉन्ड और डॉलर के बजाय दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज, बढ़ती महंगाई और वैश्विक तनाव की चिंता है।

एनएफआरए में कार्य विभाजन को लेकर सरकार तैयार कर रही नई रूपरेखा

नई दिल्ली

सरकार नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) में कार्यों के विभाजन पर विचार कर रही है। वर्तमान में एनएफआरए का कार्यकारी निकाय (अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य) सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, जिसमें ऑडिट की समीक्षा और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि कार्यों का विभाजन न होने से पूर्वाग्रह और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। अदालत ने इसे " सीज़र से सीज़र की पत्नी को अपील" की स्थिति के समान बताया। रेगस्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के वरिष्ठ पार्टनर व सेबी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि भारत का नियामक ढांचा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत से भटक गया है। जब एक संस्था नियम बनाती और निर्णय भी लेती है, तो जवाबदेही और न्याय प्रभावित होता है। उन्होंने जोर दिया कि अन्य नियामक, जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और सेबी, जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाले कार्यों को अलग रखते हैं। एनएफआरए ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

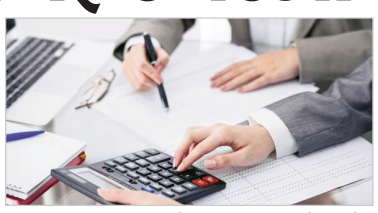

अदालत ने अंतरिम आदेश में एनएफआरए को कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन अंतिम आदेशों पर रोक लगा दी जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट आज से

कोलकाता (एजेंसी)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से यहां पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में दोनो ही टीम जीत के इरादे से उतरेंगी। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्लयूटीसी) को देखते हुए भी ये सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है। इस मैच से आक्रमक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वापसी करेंगे। वह इंग्लैंड दौरे में अंगूठे में हुए फ्रैक्चर के बाद से ही टीम से बाहर थे। ऐसे में सभी की नजरें उनके उपर रहेंगी। इसके अलावा भारत ए की ओर से शानदार प्रदर्शन करने वाले ध्रुप जुरेल भी इस मैच में खेलेंगे।

इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीकी टीम के तेज ओर स्पिन आक्रमण का सामना करना होगा। इस मैदान पर स्पिनरों को सहायता मिलती है जिसका लाभ दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर उठाना चाहेंगे। दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी आक्रमण की धार इस समय स्पिनरों पर निर्भर है और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा। दक्षिण अफ्रीकी के पास अधिकतर समय अच्छे तेज गेंदबाज रहे हैं पर इस बार टीम स्पिनरों के भरोसे है। पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में उसने सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली थी। उसमें उसके मुख्य स्पिनरों केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरान मुथुस्वामी ने 39 में से 35 विकेट लिए थे।

वहीं भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डोइशे ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का तरीका उपमहाद्वीप के गेंदबाजों के समान है। उन्होंने कहा, 'उनके पास चार स्पिनर हैं जिनमे से वे तीन को उतार सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम उपमहाद्वीप की किसी टीम के खिलाफ खेलने वाले हैं। उन्होंने कहा, 'हमने इस पर बात की है। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन वाली सीरीज से सबक लिया है। दक्षिण अफ्रीकाा के गेंदबाज हार्मर भी 1000 प्रथम श्रेणी विकेट ले चुके हैं और भारत के हालात को जानते हैं।

दस साल पहले हाशिम अमला की कप्तानी में इस गेंदबाज ने दो टेस्ट खेलकर चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और रिधिमान साहा के विकेट लिए थे। एक दशक बाद भी वह उतने ही चतुर गेंदबाज हैं। उन्होंने रावलपिंडी में में 8 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई और सीरीज ड्रॉ भी कराई। वहीं केशव महाराज सबसे सटीक और आक्रामक स्पिनरों में से एक हैं। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों और दक्षिण अफ्रीका के

स्पिनरों के बीच मुकाबला रोमांचक होना तय है।

ईडन की पिच से स्पिनरों का पहले भी सहायात मिलती रही है। वहीं बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि यह टर्निंग पिच नहीं होगी। इससे जसप्रीत बुमराह को सहायता मिल सकती है। बुमराह आम तौर पर शुरूआत में मूवमेंट और बाद में रिवर्स स्विंग देने वाली पिच पर भारत के तुरप का इक्का साबित हो सकते हैं। भारतीय टीम इस मैच में दो तेज गेंदबाजों को उतार सकता है और घरेलू मैदान होने से युवा तेज गेंदबाज आकाश दीप को भी इसमें अवसर मिल सकता है।

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम से यहां सभी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था वेस्टइंडीज की कमजोर टीम को 2-0 से हराने पर उसे विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में अधिक लाभ नहीं मिला है । ऐसे में वह इस सीरीज मे जीत चाहेगी। ऋषभ इस सीरीज से वापसी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। उनके अलावा जुरेल के बतौर बल्लेबाज खेलने से भी भारत का मध्यक्रम मजबूत हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में 16 विकेट लेने वाले वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीर में अंतर पैदा करेंगे। वहीं दूसरी ओर तेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी एडेन मार्क्रम, रियान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स , काइल वेरेने , डेवाल्ड ब्रेविस पर निर्भर करेगी। इसके अलावा टीम के पास कोर्बिन बोश, वियान मूल्डर, मार्को यानसेन जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर ये मुकाबला रोमांचक रहना तय है

टीमें इस प्रकार हैं

भारत - शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साइ सुदर्शन, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल

दक्षिण अफ्रीका - तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्क्रम, रियान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स , काइल वेरेने , डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डि जोर्जी, कोर्बिन बोश, वियान मूल्डर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, सेनुरान मुथुस्वामी , कैगिसो रबाडा, साइमन हार्मर

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा बनी आईसीसी की अक्टूबर महीने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

दुबई (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट को अच्छे प्रदर्शन और कप्तानी के लिए अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। वोल्वार्ड्ट ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान वोल्वार्ड्ट ने न केवल सबसे अधिक रन बनाए, बल्कि अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान इस खिलाड़ी ने आठ मैचों में 470 रन बनाये और उनका औसत रहा 67.14 वहीं स्ट्राइक रेट 97.91 रहा है।

वोल्वार्ड्ट ने महिला विश्व कप 2025 में आठ मैचों में कुल 470 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक और एक शतक लगाया है। वोल्वार्ड्ट ने अपने प्रदर्शन से कई मैचों में टीम को जीत दिलायी। शुरुआती मैचों में टीम की हार के बाद भी उसके फाइनल तक के सफर में इस खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन की अहम भूमिका रही। हर मैच में उन्होंने रन बनाए और टीम को मजबूत किया। इस क्रिकेटर ने 67.14 की औसत और 97.91 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये हैं।

वोल्वार्ड्ट ने कहा, 'महिला क्रिकेट के लिए यह एक ऐतिहासिक आयोजन था, और भारत में विश्व कप प्रदर्शन के बाद यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व व सम्मान की बात है। टूर्नामेंट में कई शानदार मैच हुए और खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। यह सम्मान मेरे लिए बहुत महत्व रखता है।' उन्होंने कहा कि भले ही टीम खिताब नहीं जीत सकी पर वह अपनी टीम की आक्रामक भावना और निरंतरता पर गर्व का अनुभव करता है। 'हमें पूरा भरोसा है कि अगला विश्व कप खिताब अब हमारी टीम जीतेगी।'

वोल्वार्ड्ट ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के 143 गेंदों पर 169 रन बनाये। उनकी इस पारी के बल पर ही टीम पहली बार महिला विश्व कप फाइनल में पहुंची। यह पारी न केवल टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक रही, बल्कि उनके करियर का भी मील का पत्थर साबित हुई।

लखनऊ सुपर जाइंट्स से रिलीज हो सकते हैं शार्दुल ठाकुर, इस टीम के लिए खेलेंगे आईपीएल 2026

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ एक ऑलकैश ट्रेड डील के तहत समझौता कर लिया है। बताया गया है कि दोनों फ्रेंचाइजियों ने IPL को अपनी रुचि के बारे में जानकारी दी है और जरूरी औपचारिकताओं के पूरा होते ही इस सौदे को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी। यह नया बदलाव दर्शाता है कि शार्दुल IPL के इतिहास में एक अद्वितीय कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। यह उनके IPL करियर का तीसरा ट्रांसफर होगा। 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट ने उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब (जो अब पंजाब किंग्स है) से अधिग्रहित किया था। इसके बाद 2023 के सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से अपने साथ शामिल किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों बार यह व्यापार पूरी तरह से ऑल कैश डील पर आधारित था। ठाकुर 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे और काउंटी चैम्पियनशिप में ऐसेक्स से जुड़ने वाले थे, लेकिन LSG ने उन्हें मोहसिन खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में चुना था। उस समय स्स्त्र के मेंटॉर जहीर खान का यह फैसला अच्छा निवेश साबित हुआ था। ठाकुर ने IPL 2025 के शुरुआती दो मैचों में छह विकेट लिए थे। हालांकि इसके बाद उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने कुल 10 मैचों में 13 विकेट लिए। साथ ही उनकी इकॉनमी रेट 11.02 रही। मुम्बई इंडियंस की टीम में फिर से शामिल होना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। ठाकुर 2010 से 2012 तक मुंबई टीम के सपोर्ट बोलर रहे थे और घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम के कप्तान भी रह चुके हैं।

डफी की कहर बरपाती गेंदबाजी, न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को धोकर 3-1 से सीरीज जीती

डुनेडिन (न्यूजीलैंड) (एजेंसी)। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में पांच मैचों की टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ, मिशेल सैंटनर की अगुवाई वाली टीम ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। चौथा टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद 2-1 की अजेय बढ़त हासिल करने के बाद, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने कीवी टीम को जोरदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने तीन विकेट जल्दी चटकाए और विपक्षी टीम के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। वेस्टइंडीज का स्कोर महज 2.4 ओवर में 21/4 हो गया। इसके बाद, वेस्टइंडीज वापसी नहीं कर सका और केवल 140 रन ही बना सका। डफी ने 4-35 के प्रभावशाली गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए, जबकि रोस्टन चेस 32 गेंदों में 38 रन बनाकर मेहमान टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। रोमारियो शेफर्ड ने भी अंत में बढ़त हासिल की और 22 गेंदों में 36 रन बनाकर वेस्टइंडीज को अंत में

सम्मानजनक स्कोर दिया। न्यूजीलैंड ने तेजी से लक्ष्य का पीछा किया। सलामी बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन और डेवोन कॉनवे ने शानदार शुरुआत की और सिर्फ सात ओवर में 69 रन बनाकर मैच को वेस्टइंडीज की पहुंच से दूर कर दिया। रॉबिन्सन ने आक्रामक 45 रनों के साथ आक्रमण का नेतृत्व किया, जबकि कॉनवे ने धैर्यपूर्वक पारी को संभाला, 47 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाई। मार्क चैपमैन ने 13 गेंदों में तेजी से 21 रन जोड़कर गति बनाए रखी। दोनों टीमें अब तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में आमने-सामने होंगी, जहाँ वेस्टइंडीज़ को अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, रेमन सिमंड्स और जेडियाह ब्लेड्स की चोटों के कारण सेवाएँ नहीं मिलेंगी। पहला एकदिवसीय मैच रविवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। संक्षिप्त स्कोर- वेस्टइंडीज़- 18.4 ओवर में 140-10 (रोस्टन चेज़ 38, रोमारियो शेफर्ड 36, जैकब डफी 4-35) और न्यूज़ीलैंड- 15.4 ओवर में 141-2 (डेवोन कॉनवे 47*, टिम रॉबिन्सन 45, शमर स्प्रिंगर 1-8)।

सिंगापुर के जिया हेंग को हराकर जापान मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन

कुमामोतो (जापान)। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने गुरुवार को यहां सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके कुमामोतो मास्टर्स जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता सेन ने 39 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी तेह को 21-13, 21-11 से हराया। विश्व के 15वें नंबर के खिलाड़ी सेन का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू से होगा। लक्ष्य ने पहले गेम में 8-5 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद तेह ने कुछ देर के लिए 10-9 की मामूली बढ़त हासिल कर ली, लेकिन ब्रेक तक भारतीय खिलाड़ी ने फिर बढ़त बना ली। दोनों खिलाड़ियों के बीच 14-13 के स्कोर तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन इसके बाद लक्ष्य ने लगातार सात अंक बनाकर पहला गेम अपने नाम कर दिया। लक्ष्य ने दूसरे गेम में शुरू से अच्छा प्रदर्शन किया और जल्द ही 5-0 की बढ़त बना ली। उन्होंने इंटरवल तक 11-3 की बढ़त बनाकर अपने प्रतिद्वंदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद भी अपनी लय बरकरार रखी और आसानी से मैच जीता। भारत के एक अन्य खिलाड़ी एचएस प्रणय का सामना डेनमार्क के रासमस गेम्के से होगा।

भारतीय सरजमीं पर जीतना विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद दूसरे नंबर पर होगा : बावुमा

कोलकाता। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराने की संभावना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही होगा। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी। लेकिन बावुमा का मानना है कि 2023 में कोच शुक्री कॉनराड के कार्यभार संभालने के बाद से इस टीम को टेस्ट श्रृंखला में हार का सामना नहीं करना पड़ा है और अब उनकी टीम इतनी परिपक्व और आत्मविश्वास से भरी है कि वह कड़ी चुनौती पेश करके भारत में अब तक की अपनी दूसरी श्रृंखला जीत सकती है। ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले बावुमा ने कहा, 'मुझे लगता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जीतना इसके बाद दूसरे नंबर पर होगा। यह ऐसा कुछ है जो हम लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसलिए महत्वाकांक्षा के मामले में यह निश्चित रूप से ऊपर है।' बावुमा ने कहा, 'हम चुनौती की गंभीरता को समझते हैं। इसलिए हम इसकी अहमियत जानते हैं।' दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने कहा, 'हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं। दोनों टीमों को देखते हुए यह रोमांचक होना चाहिए। भारतीय टीम में शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़े कम अनुभवी भी हैं। इसी तरह हमारी टीम भी है, हमारे खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करना चाहते हैं।'

कप्तानी के लिए अच्छी पर्सनैलिटी और अंग्रेजी बोलना जरुरी नहीं : अक्षर पटेल

-लोगों को अपनी धारणा बदलनी होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम के स्पिर ऑलराउंडर व दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा है कप्तानी को लेकर एक ऐसी धारणा बन गयी है जो सही नहीं है पर ये कई साल से चली आ रही अक्षर के अनुसार लोग मानते है कि अच्छी पर्सनैलिटी और अंग्रेजी बोलना कप्तानी के लिए जरुरी है। वहीं केवल इस आधार पर किसी को कप्तानी के लिए अयोग्य मान लेते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता। अक्षर कप्तानी को लेकर लोगों की इस धारणा से नाराज है। उन्होंने कहा कि कप्तानी के लिए किसी खिलाड़ी की पर्सनैलिटी और अंग्रेजी बोलने की क्षमता को लोग वरीयता देते हैं पर क्रिकेट से जुड़े कौशल को नहीं देखते हैं। अक्षर ने कहा, 'लोग कहना शुरू कर देते हैं- ओह, वह कप्तानी मटैरियल नहीं है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। वह कैसे बात करेगा? ये है, वो है।' साथ ही कहा, अरे, कप्तान का काम सिर्फ बात करना थोड़े होता है। कप्तान का काम खिलाड़ी को जानना होता है और उससे उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल करना होता है। ये जानना होता है। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, ये समझना होता है। कप्तान को पता होता है कि हमारे पास ये खिलाड़ी है और मुझे उससे कैसे अच्छा प्रदर्शन लेना है। इसके अलावा मैच के हालात के अनुसार किये गेंदबाजी देनी है। अक्षर ने आगे कहा, 'लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छा इंग्लिश बोलना चाहिए। धारणा लोगों की अपनी सोच के आधार पर बनी है। मैंने इस साल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की और मुझे बहुत सारी तारीफ मिली। मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा और भी होगा और आने वाले समय में अभी और ज्यादा बदलाव आएंगे।' उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी व्यक्तिगत सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत है। ये सोचना बंद कीजिए कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वह इंग्लिश बोल सकता है तो वह कैप्टन मटैरियल है।

गुजरात छोड़ मुंबई इंडियन्स से जुड़ेंगे वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर, मुंबई इंडियंस ने खर्च किए 2.6 करोड़

नई दिल्ली । गुजरात टाइटन्स ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड को आईपीएल 2026 से पहले दो करोड़ 60 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस (MI) को 'ट्रेड' किया। आईपीएल ने एक बयान में कहा, 'गुजरात टाइटन्स द्वारा 2.6 करोड़ रुपए में खरीदे गए रदरफोर्ड अपनी मौजूदा फीस पर मुंबई इंडियन्स में शामिल होंगे।' वेस्टइंडीज के इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 44 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आंद्रे रसेल के साथ 139 रन की साझेदारी की थी। रदरफोर्ड ने अब तक 23 आईपीएल मैच खेले हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में दिल्ली कैपिटल्स और 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया था। वह 2020 में मुंबई इंडियन्स और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे लेकिन उन सत्र के दौरान एकादश का हिस्सा नहीं बन पाए।

आईपीएल2026 से पहले मोहम्मद शमी त्रिकोणीय रस्साकशी के केंद्र में

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोहम्मद शमी, जो हाल ही में भारतीय टीम में चयन न होने के कारण चर्चा में हैं, 2026 के आईपीएल सीजन से पहले त्रिकोणीय रस्साकशी के केंद्र में हैं। इस अनुभवी तेज गेंदबाज के लिए कई फ्रेंचाइजी रुचि दिखा रही हैं, और हो सकता है कि उन्हें उनमें से किसी एक के साथ ट्रेड कर दिया जाए।

हाल ही में पता चला है कि सनराइजर्स हैदराबाद मौजूदा मांग का सर्वोत्तम उपयोग करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। 35 वर्षीय तेज गेंदबाज, जो अपने 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में लंबे समय तक भारतीय आक्रमण का अगुआ रहा है, जिसमें 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय शामिल हैं, को लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा खरीदा जा रहा है और दिल्ली कैपिटल्स भी उतनी ही उत्सुकता दिखा रही है। अब देखना यह होगा

कि एसआरएच प्रबंधन इस स्थिति से कैसे निपटता है। अगर यह सौदा होता है, तो यह एकतरफा होगा।

नीलामी पूल में शामिल होने की भी संभावना है, लेकिन पूरी तरह से नकद लेन-देन वाला विकल्प ज़्यादा संभावित लगता है। शमी को जेद्दा में हुई पिछली मेगा नीलामी में एसआरएच ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन मामूली रहा - 56.17 के निराशाजनक औसत और 11.23 के इकॉनमी रेट से सिर्फ छह विकेट, जबकि उनके करियर के आंकड़े क्रमशः 28.19 और 8.63 रहे हैं।

उन्होंने कुल 119 आईपीएल मैचों में 133 विकेट लिए हैं, जिनमें से ज़्यादातर विकेट उन्होंने 2022 और 2023 में गुजरात टाइटन्स के लिए दो शानदार सीजन के दौरान लिए थे, जब उन्होंने कुल मिलाकर 48 विकेट (क्रमशः 20 और 28) लिए थे। चोट के कारण वह पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। दिल्ली कैपिटल्स की शमी में कितनी गहरी दिलचस्पी है, इसका अंदाज़ा सौरव गांगुली की इस तेज गेंदबाज पर हालिया टिप्पणियों से लगाया जा सकता है। 'मुझे यकीन है कि चयनकर्ता नजर रख रहे हैं और मोहम्मद शमी और चयनकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो फिटनेस और कौशल के मामले में, यह वही मोहम्मद शमी है जिसे हम जानते हैं।'

दिल्ली कैपिटल्स प्रबंधन के सदस्य गांगुली ने कुछ दिन पहले मीडिया में कहा था, 'इसलिए, मुझे वास्तव में कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत के लिए टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते। क्योंकि यह कौशल बहुत बड़ा है।' शमी ने इस साल मार्च में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, और उनकी फिटनेस की स्थिति एक गर्म विषय बन गई, जिसमें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और खुद खिलाड़ी सार्वजनिक रूप से बयानबाजी में शामिल रहे। शमी ने इस सीजन में बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी मैचों में अपनी फिटनेस साबित की है और पिछले तीन रणजी मैचों में 15 विकेट लिए हैं।

2026 सत्र के लिए बोल्ट और दीपक चाहर को रिटेन नहीं करेगी मुम्बई इंडियंस : हेडन

नई दिल्ली । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सत्र में मुंबई इंडियंस की टीम तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर को बाहर कर देगी। हेडन ने कहा, 'मुंबई इंडियंस के पास एक संतुलित अंतिम ग्यारह है पर इसके बाद भी उसे जीत के लिए उसे कुछ कठिन फैसले लेने होंगे, जिसमें न्यूजीलैंड के बोल्ट को रिलीज करना भी शामिल है।' बोल्ट को पिछले सत्र में मुंबई की टीम ने 12.50 करोड़ में खरीदा था और उन्होंने सीजन में कुल 22 विकेट लिए थे। बोल्ट पावर प्ले में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में टीम के लिए उन्हें बाहर करना कठिन फैसला होगा। ये भी हो सकता है कि मुंबई उन्हें मिनी निलामी में कम कीमत पर खरीदे। बोल्ट के अलावा मुंबई इंडियंस से दीपक चाहर भी बाहर होंगे। हेडन का मानना है कि चाहर को रिलीज कर टीम कम पैसों में किसी अच्छे तेज गेंदबाज को नीलामी में शामिल कर सकती है। चाहर को मुंबई की टीम ने आईपीएल 2025 में 9.25 करोड़ में खरीदा था पर वह टीम के लिए फायदेमंद नहीं रहे। वह सत्र में केवल 11 विकेट ले पाए थे। इसी को देखते हुए हेडन का मानना है कि चाहर को रिलीज किया जाएगा जिससे मिनी नीलामी में किसी युवा खिलाड़ियों को बैक अप के तौर पर खरीदा जा सके। पांच बार की विजेता मुम्बई इंडियंस का पिछला सत्र अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में वह इस बार टीम संयोजन में कमी नहीं रखना चाहेगी।

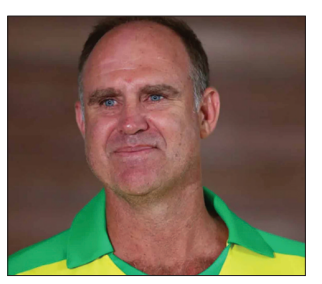

सानिया मिर्जा का खुलासा, तलाक के बाद गहरे डिप्रेशन में चली गई थी, पैनिक अटैक भी आए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पहली बार अपने जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में खुलासा किया है। शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया गहरे डिप्रेशन और पैनिक अटैक से जूझ रही थीं। इस मुश्किल समय में बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने उनकी भावनात्मक रूप से मदद की और उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी। अपने नए यूट्यूब शो ÷सर्विंग इट अप विद सानिया÷ के पहले एपिसोड में सानिया ने बताया कि कैसे फराह ने उन्हें जीवन के सबसे नाजुक पलों से उबरने में साथ दिया।

तलाक के बाद बिखर गई थीं सानिया मिर्जा

सानिया मिर्जा ने साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी। इस रिश्ते ने शुरुआत से ही दोनों देशों में खूब सुर्खियां बटोरीं। 2018 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने, लेकिन साल 2024 में शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी कर ली, जिससे यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस टूटे रिश्ते का असर सानिया पर गहराई से पड़ा। उन्होंने बताया कि तलाक के बाद उन्हें पैनिक अटैक आने लगे और वे लंबे समय तक डिप्रेशन में रहीं। उस दौर को सानिया ने अपनी जिंदगी का 'सबसे बुरा समय' बताया।

फराह खान बनीं मुश्किल वक्त में सहारा

अपने नए टॉक शो 'सर्विंग इट अप विद सानिया' के पहले एपिसोड में सानिया ने फराह खान के साथ बातचीत में इस घटना का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, 'मैं कैमरे पर यह नहीं बताना चाहती, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं बुरी तरह टूट गई थी। आप (फराह खान) मेरे सेट पर आई थीं और उसके बाद मुझे एक लाइव शो में जाना था। मैं कांप रही थी। अगर आप वहां नहीं आतीं, तो शायद मैं वह शो नहीं कर पाती। आपने मुझसे कहा था, 'चाहे कुछ भी हो, तुम यह शो करोगी।' सानिया की इन बातों से यह साफ़ झलकता है कि फराह खान ने उस कठिन समय में उनके लिए एक भावनात्मक स्तंभ का काम किया।

फराह खान ने याद किया वो दिन

फराह खान ने भी उस घटना को याद करते हुए बताया कि सानिया को परेशान देखकर वे खुद भी घबरा गई थीं। उन्होंने कहा, 'मुझे उस दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन जब मैंने सानिया को उस हालत में देखा तो सब कुछ छोड़कर भागी चली आई। मैं पजामा और चप्पल में वहां पहुँची, क्योंकि मुझे उनकी चिंता थी।' फराह ने बताया कि सानिया को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने का नाम है।

सिंगल मदर के रूप में सानिया की ताकत की सराहना

फराह खान ने बातचीत के दौरान सानिया की सिंगल मदर के रूप में भूमिका की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'अकेले बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है। आपको काम भी करना पड़ता है और एक मां के तौर पर बेटे को समय भी देना पड़ता है। यह दोगुनी मेहनत का काम है, लेकिन सानिया इसे खूबसूरती से निभा रही है।'

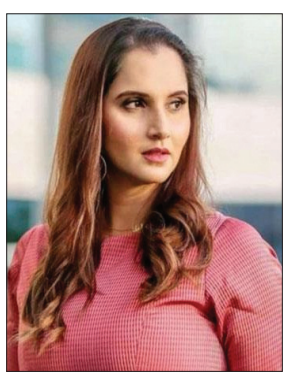

सानिया आज अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक की परवरिश अकेले कर रही हैं और वे अपने पेशेवर जीवन में भी सक्रिय हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

तुर्की का मिलिट्री विमान जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त, 20 जवानों की मौत की आशंका

अंकारा, एजेंसी। तुर्की का एक सैन्य मालवाहक विमान अजरबैजान की सीमा के निकट जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल सहित 20 सैन्यकर्मी सवार थे। तुर्की और जॉर्जिया के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन हताहतों की सटीक संख्या के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तुर्की के समाचार चैनलों पर दिखाए गए वीडियो फुटेज में विमान को तेजी से नीचे गिरते हुए और सफेद धुएं के गुबार के साथ दुर्घटनाग्रस्त होते देखा गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की कि यह सी-130 विमान अजरबैजान से उड़ान भरकर तुर्की लौट रहा था, जब यह हादसे का शिकार हो गया। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और 'मृतकों' के प्रति संवेदना जाहिर की, जिससे संकेत मिलता है कि कई लोगों की जान जा चुकी हो सकती है। मंत्रालय के अनुसार, विमान में 20 सैन्यकर्मी सवार थे, जिनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अजरबैजान और जॉर्जिया के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से खोज व बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना सिग्नाघी नगरपालिका क्षेत्र में घटी, जो अजरबैजान सीमा के करीब स्थित है। विभाग ने मामले की जांच भी आरंभ कर दी है। एर्दोगन ने कहा कि वे इस हादसे से 'बहुत दुखी' हैं और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। बता दें कि सी-130 हरक्यूलिस विमान अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित चार इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। इसे छोटे और अपर्याप्त रनवे से आसानी से उड़ान भरने व उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी कार्य माल ढोना, सैनिकों और उपकरणों का परिवहन करना है। इसके अलावा, इसे गनशिप, हवाई हमले और टोही अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाता है।

मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया, चीन की चुनौती से निपटने में जुटे क्वाड देश

कैनबरा, एजेंसी। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत, जापान और अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार में शिरकत कर रहे हैं। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। मालाबार युद्धाभ्यास 10 नवंबर को शुरू हुआ था और 18 नवंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के युद्धाभ्यास में शामिल होने के बाद अब क्वाड के चारों सदस्य देश मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि 'रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का ईंझ श्रेणी की फ्रिगेट एचएमएएस बालाराट और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एअर फोर्स के पी-8ए पोसायडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। पोसायडन गुआम के एंडरसन एअर फोर्स बेस से संचालित होगा।' ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ जॉइंट ऑपरेशन वाइस एडमिरल जस्टिन जोंस ने बताया कि मालाबार युद्धाभ्यास बढ़ती क्षेत्रीय साझेदारी और लगातार बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की अहमियत बताता है। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। पहली बार अमेरिका और भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए। ये चारों देश ही क्वाड संगठन का हिस्सा हैं। ऐसे में मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों का युद्धाभ्यास बन गया है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चीन की चुनौती से निपटने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन के मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मालाबार युद्धाभ्यास अहम है। युद्धाभ्यास में भाग ले रहे ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज के कमांडर डीन यूरेन ने कहा कि यह हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच अंतरसंचालन को बेहतर करने का यह बेहतरीन अवसर है। क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ युद्धाभ्यास से हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे।

चीन का 758 मीटर लंबा नया होंगची ब्रिज ढहा, उद्घाटन के 44 दिन बाद हादसा

बीजिंग, एजेंसी। चीन के सिचुआन प्रांत में हाल ही में शुरू हुआ होंगची ब्रिज आंशिक रूप से ढह गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया था और इसकी लंबाई करीब 758 मीटर है। सोमवार दोपहर पुल के आसपास की पहाड़ी ढलानों और सड़कों पर दरारें दिखाई दीं। पहाड़ की जमीन खिसकने लगी तो प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पुल को तत्काल बंद कर दिया। मंगलवार दोपहर हालात और बिगड़ गए। पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी खिसकने के बाद पुल का एक हिस्सा टूटकर ढह गया। अब तक किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं मिली है। वीडियो में धूल का गुबार उठता दिखाई देता है और पुल के खंभे टूटकर नीचे पत्थरों और नदी में गिरते नजर आते हैं। यह पुल इसी साल पूरा हुआ था।

सादरिस्ट का बहिष्कार, कम वोटिंग और कड़ी सुरक्षा; क्या संदेश दे रहा है बगदाद का जनादेश?

बगदाद, एजेंसी। इराक में मंगलवार को संसदीय चुनाव हुए, जो कड़ी सुरक्षा और एक बड़े राजनीतिक गुट के बहिष्कार से प्रभावित रहे। मतदान के दौरान हिंसा की सिर्फ एक बड़ी घटना सामने आई, जो कि उत्तरी शहर किर्कुक में दो दलों के समर्थकों के बीच झड़प में दो पुलिसकर्मी मारे गए। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत मतदाताओं में से 55% ने वोट डाला, लेकिन कुल 32 मिलियन योग्य मतदाताओं में से सिर्फ 21.4 मिलियन ने ही मतदाता कार्ड बनवाए, जो 2021 के चुनाव में 24 मिलियन से कम है।

बता दें कि यह चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं। उदाहरण के तौर पर गाजा और लेबनान में युद्ध, इस्राइल-ईरान संघर्ष और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के पतन जैसे घटनाक्रमों के बीच। ऐसे में अमेरिका भी इराक सरकार पर ईरान समर्थक सशस्त्र गुटों के प्रभाव को कम करने का दबाव बना रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने कहा कि यह चुनाव जनता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2003 के बाद सिर्फ एक प्रधानमंत्री को ही दोबारा मौका मिला है।

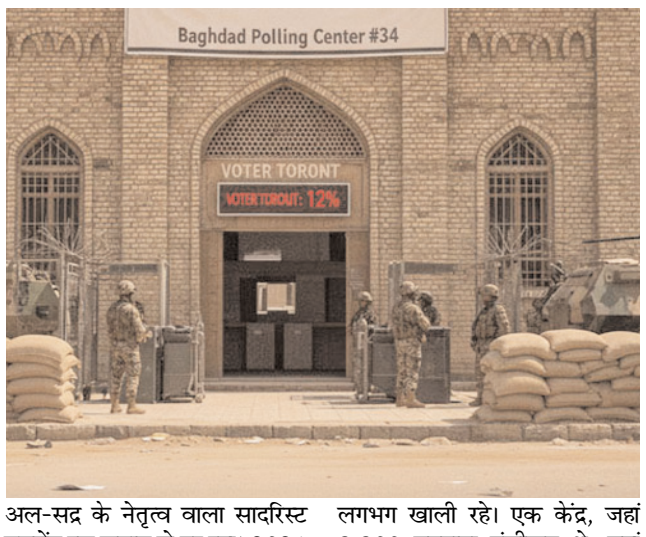

सादरिस्ट मूवमेंट का बहिष्कार : प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सद्र के नेतृत्व वाला सादरिस्ट मूवमेंट इस चुनाव से दूर रहा। 2021 में इस गुट ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, लेकिन सरकार गठन पर सहमति न बनने के बाद उसने संसद से इस्तीफा दे दिया और अब पूरे राजनीतिक सिस्टम का बहिष्कार कर रहा है। सदर सिटी (बगदाद के बाहरी इलाके) में सुरक्षा बेहद कड़ी थी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और विशेष बलों की तैनाती थी। वहां एक बड़ा बैनर लगा था, जिसमें अल-सद्र सैन्य वर्दी में हथियार लिए नजर आ रहे थे, साथ में लिखा था- मेरे लोग सदर सिटी में बहिष्कार कर रहे हैं। खास बात ये रही है कि मतदान केंद्र खुले तो थे, लेकिन लगभग खाली रहे। एक केंद्र, जहां 3,300 मतदाता पंजीकृत थे, वहां कुछ घंटों में केवल 60 लोगों ने वोट डाला। केंद्र के निदेशक अहमद अल-मुसावी ने कहा कि सादरिस्ट बहिष्कार का बड़ा असर पड़ा है। पहले लंबी कतारें लगती थीं, अब सन्नाटा है। स्थानीय निवासी सबीह दाखिल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि शायद नए नेता जीवन स्तर सुधारें। जबकि दूसरे निवासी राफिद अजील ने कहा कि यह सरकार भ्रष्ट है, पहले भी भ्रष्ट थी, आगे भी वैसी ही होगी।

किर्कुक में तनाव और हिंसा, समझिए कारण : मतदान से पहले रात में किर्कुक में हिंसा भड़क उठी। यहां अरब, कुर्द, शिया और तुर्कमान समुदाय रहते हैं और यह इलाका लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद का केंद्र रहा है। रात 2 बजे के करीब दो गुटों में झगड़ा हुआ जो बाद में गोलीबारी में बदल गया। इसमें दो पुलिसकर्मी मारे गए और दो नागरिक घायल हुए। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, झगड़ा कुर्द पार्टी (पीयूके) और इराकी तुर्कमान फ्रंट के समर्थकों के बीच हुआ। सुबह तक स्थिति शांत हुई और धीरे-धीरे लोग वोट डालने पहुंचे। हालांकि, कई मतदाताओं ने राजनीतिक उदासीनता जताई। 60 वर्षीय नूरअदीन सालेह ने कहा, 'हम सिर्फ चेहरों को बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता। अस्सीरी अल्पसंख्यक की बैन बहनम ने भी कहा, 'उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम वोट डालने आते हैं।

भ्रष्टाचार और कानूनी विवाद : मतदान से पहले भ्रष्टाचार और वोट खरीदने के कई आरोप लगे। सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते 46 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से वोटर कार्ड खरीद-बेच रहे थे। उनके पास से 1,841 कार्ड बरामद हुए।इराक के सुप्रीम ज्युडिशियल काउंसिल के प्रमुख ने भी कहा कि चुनाव की तारीख संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसे पहले 24 नवंबर तय किया गया था, बाद में बदलकर 12 नवंबर कर दिया गया।

कंबोडिया और थाईलैंड में फिर छिड़ेगी जंग? थाई सेना ने रद्द किया ट्रंप का शांति समझौता

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड की सेना ने मंगलवार को कंबोडिया पर विवादित सीमा क्षेत्र में नई बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया। थाईलैंड ने दावा किया कि इन बारूदी सुरंगों के चलते उसके कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीमा पर लैंडमाइन्स बिछाए जाने को थाईलैंड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित शांति समझौते का उल्लंघन बताया। थाईलैंड की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि फोरेंसिक अधिकारियों ने सोमवार (10 नवंबर,2025) को कंथारलक जिले में बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र की जांच-पड़ताल की। इस दौरान अधिकारियों को धमाके से बना एक गड्ढा और तीन अन्य बारूदी सुरंगों का पता चला। सीमा पर गश्त के दौरान 4 थाई सैनिक घायलथाई सेना की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया था कि सीमा पर गश्त करने के दौरान लैंडमाइन पर पैर पड़ने की वजह से चार सैनिक घायल हो गए। इनमें से एक सैनिक ने अपना पैर भी गंवा दिया। बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक मेजर जनरल विनथाई ने कहा, ''इस तरह की घटना संघर्ष को कम करने में कंबोडिया के दोहरे रवैये को दर्शाता है। ये शत्रुता को भी दर्शाता है, जो संयुक्त रूप से माने गए समझौते का भी उल्लंघन है। कंबोडिया ने आरोपों को किया खारिज कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार की देर रात थाईलैंड के आरोपों को खारिज कर दिया। कंबोडिया की ओर से कहा गया कि कंबोडिया के गृह युद्ध के दौरान की एक पुरानी बारूदी सुरंग में धमाके की वजह से सोमवार को थाई सैनिक घायल हुए। कंबोडिया की ओर से कहा गया कि उसकी ओर से सीमा पर कोई भी नई लैंडमाइंस नहीं बिछाई गई हैं, जो आम नागरिकों के लिए खतरा बनें। थाईलैंड पर कंबोडिया ने जड़ा ये आरोप कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने शांति समझौते की शर्तों और जेनेवा कन्वेंशन का सख्ती से पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रालय ने थाईलैंड की ओर से कंबोडिया के साथ तमाम गतिविधियां सस्पेंड करने पर भी चिंता जताई। इसमें विवादित सीमा क्षेत्र से बड़े हथियारों को हटाने और कंबोडियाई युद्धबंदियों को छोड़े जाने पर सहमति बनी थी।

संयुक्त राष्ट्र चीफ गुटेरस ने दिल्ली धमाके पर दुख जताया, जांच की मांग की

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया है। उनके प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि भारत सरकार और लोगों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी तरह जांच जरूरी है।

मंगलवार को हुई इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता से इस मामले और इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बारे में सवाल पूछे गए थे। इस्लामाबाद के हमले पर उन्होंने कहा कि महासचिव इस घटना से बेहद दुखी हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गुटेरस ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा की हर घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को सज़ा मिले। इसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मंगलवार को एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस वाहन के पास खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत और 36 लोग घायल हुए।

जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह के बिना चुनाव नहीं: बांग्लादेश की इस्लामी पार्टी : ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने मंगलवार को फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव का कड़ा विरोध किया और कहा कि जब तक जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह कर उसे 'कानूनी आधार' नहीं दिया जाता, तब तक चुनाव नहीं हो सकता। ढाका में अपने सात इस्लामी सहयोगियों के साथ आयोजित एक रैली में जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा, इस देश के स्वतंत्रता-प्रेमी लोगों का एक ही संदेश है-आम चुनाव से पहले एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह होना चाहिए। यह रैली जमात की ताकत दिखाने का एक प्रयास मानी जा रही है।

11 साल बाद हमास ने इस्राइल को लौटाया सैनिक का शव, अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों की भीड़

यरुशलम, एजेंसी। मध्य इस्राइल में मंगलवार (11 नवंबर,2025) को 11 साल बाद गाजा से लौटे इस्राइली सैनिक के शव के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैनिक के अंतिम संस्कार के दौरान हाथों में इस्राइल का झंडा लिए हुए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसके चलते श्मशान और आस-पास की तमाम गलियां जाम हो गई। लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों के लिए भावुक कर देने वाला पल था। दरअसल, लेफ्टिनेंट के परिवार ने उनके शव को वापस इस्राइल लाने के लिए एक बड़ा सार्वजनिक अभियान चलाया था। हमास ने 9 नवंबर, 2025 को उनके शव का अवशेष इस्राइल को वापस भेजा। वहीं 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले में चार बंधकों के शवों को गाजा ले जाने के बाद इस्राइल के साथ युद्ध छिड़ गया था। ये शव अभी भी गाजा में ही हैं। 2014 में इस्राइल और हमास के बीच युद्धविराम के एलान के दो घंटे बाद 23 साल के गोल्डिन की मौत हो गई थी। कई वर्षों तक गोल्डिन और एक अन्य सैनिक ओरोन शॉल के पोस्टर इस्राइल की गलियों में दिखते थे। वहीं, उनके परिवारों की ओर से शवों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इस्राइली सेना की ओर से बहुत पहले साफ कर दिया गया था कि गोल्डिन की हत्या हो चुकी है और सबूत के तौर पर सुरंग में उसकी खून से सनी शर्ट बरामद की गई थी। बीते वर्षों में गोल्डिन के शव की पहचान होने के बाद उनके परिजनों ने कई बार निराशा जाहिर की। परिजनों ने कहा था कि उनके बेटे का शव न इस्राइली सेना और न ही कोई अन्य वापस लेकर आया। इसे एक तरह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना के तौर पर देखा गया। वहीं, नेतन्याहू ने हालिया कैबिनेट बैठक में कहा, ''इस्राइली सैनिक का शव हमास के कब्जे में लंबे समय तक रहने से परिवार को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी। अब वे उसका अंतिम संस्कार कर सकेंगे।'' गौरतलब है कि ओरोन शॉल का शव साल की शुरुआत में ही इस्राइल वापस आ गया था। गोल्डिन के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''हैदर जंग लड़ने गया था और इस्राइली सेना ने उसे छोड़ दिया। इस्राइली सेना ने हमारे और उसके मानवीय अधिकारों को खत्म कर दिया।'' गोल्डिन के शव को वापस लाने की शुरुआती कोशिशों में दर्जनों फलस्तीनी मारे गए थे। फलस्तीन की ओर से इसे अंधाधुंध गोलीबारी बताया गया था। गोल्डिन के शव को पाने के लिए इस्राइल ने हैनीबेल प्रोटोकॉल लागू किया था। इसके तहत इस्राइली सेना को भारी हथियार और सैन्यबल के इस्तेमाल की छूट मिलती है। गोल्डिन की तलाश में इस्राइली सेना ने गाजा शहर में भीषण गोलीबारी और एयरस्ट्राइक की थीं, जिनमें 110 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। 2016 में भारी आलोचना के बाद हैनीबेल प्रोटोकॉल को रद्द कर दिया गया था। 2014 में हुई इस्राइल और हमास की जंग में 2200 फलस्तीनियों की मौत हो गई थी।

एच-1बी वीजा पर नरम पड़े ट्रंप; कहा- अमेरिका को चाहिए टैलेंट, सिर्फ बेरोजगारों पर निर्भर नहीं रह सकते

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अब तक के सख्त रुख से पीछे हटते हुए कहा है कि देश को विदेशी कुशल लोगों की जरूरत है। उन्होंने माना कि अमेरिका केवल लंबे समय से बेरोजगार बैठे लोगों पर निर्भर रहकर अपनी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अपने उद्योगों और रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'मैं सहमत हूं कि हमें अमेरिकी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमें यह टैलेंट भी लाना होगा। अमेरिका को दुनिया में आगे बनाए रखने के लिए ये जरूरी है।'

नई वीजा नीति में बड़ा बदलाव : इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर महीने में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद एच-1बी वीजा आवेदन की फीस में बड़ा इजाफा किया गया। अब नए वीजा के लिए 1,500 डॉलर की जगह 1 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर के बाद दाखिल किए गए सभी नए आवेदन या 2026 की वीजा लॉटरी में शामिल होने वालों पर लागू होगा। हालांकि, जो लोग पहले से वीजा पर हैं या जिनके आवेदन पहले दिए गए हैं, वे इस नए नियम से प्रभावित नहीं होंगे।

हर बेरोजगार को नहीं सिखाया जा सकता मिसाइल बनाना : जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अमेरिका में पहले से काफी प्रतिभाशाली लोग हैं, तो ट्रंप ने कहा, 'नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ खास स्किल्स ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं हैं। आप बेरोजगारों को सीधा नहीं कह सकते कि 'चलो, अब मिसाइल बनाना सीखो।' उन्हें ट्रेनिंग और अनुभव चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉर्जिया राज्य का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक हुंडई बैटरी फैक्ट्री में जब दक्षिण कोरिया से आए कुशल मजदूरों को वापस भेजा गया, तो उत्पादन में भारी दिक्कतें आईं। उन्होंने कहा, 'बैटरियां बनाना बहुत जटिल और खतरनाक काम है। कई विस्फोट की घटनाएं होती हैं। कोरिया से आए लोग इस काम में माहिर थे और वहीं से अमेरिकी कर्मचारियों को सिखा रहे थे। जब उन्हें भेज दिया गया, तो पूरी व्यवस्था ठप हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान उनके पुराने रुख से बिल्कुल अलग माना जा रहा है। पहले ट्रंप विदेशी कामगारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं और कहते थे कि इससे अमेरिकी नौकरियां छिनती हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद कहा है कि 'देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने में कई साल लगेंगे। तब तक हमें विशेषज्ञों को लाना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट का एसएनएपी फूड सहायता पर रोक का आदेश जारी, शटडाउन के बीच अब कैसे गहराया भूख का संकट?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के चलते अब भूख का संकट गहरा होता दिख रहा है। कारण है कि एक तरफ जहां शटडाउन के जल्दी खत्म होने की बात खूब सुर्खियां बटोर रही है। तो दूसरी ओर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) यानी खाद्य सहायता योजना के पूर्ण भुगतान पर लगी अस्थायी रोक को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अदालत का यह आदेश गुरुवार रात तक प्रभावी रहेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब संकेत मिल रहे हैं कि सरकारी शटडाउन जल्द खत्म हो सकता है और इससे करोड़ों लोगों को मिलने वाली फूड सहायता बहाल हो सकती है।

SNAP कार्यक्रम के तहत करीब 4.2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को खाने-पीने की चीजें खरीदने में मदद मिलती है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से राज्यों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ राज्यों में लाभार्थियों को पूरा मासिक राशन मिल चुका है, जबकि कुछ को आंशिक या बिल्कुल नहीं मिला। अदालत ने फिलहाल कोई बड़ा कानूनी फैसला देने से परहेज करते हुए स्थिति को अस्थायी रूप से यथावत रखा है।

जरूरतमंदों की बढ़ी मुश्किलें, समझिए कैसे : अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कुछ लोगों को नवंबर का पूरा लाभ मिल गया, लेकिन कई लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला। 41 वर्षीय जिम मलियार्ड जो अपनी बीमार पत्नी और बेटी की देखभाल करते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले दो हफ्तों से 350 डॉलर की मासिक एसएनएपी सहायता नहीं मिली। अब उनके पास सिर्फ 10 बचे हैं और परिवार चावल व इंस्टेंट नूडल्स पर गुजारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर रात खर्च गिनता हूं ताकि परिवार का पेट चल सके। चिंता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इस संकट के बीच कई आम नागरिक मदद के लिए आगे आए हैं। न्यूयॉर्क की शिक्षिका एशली ऑक्सेनफोर्ड ने अपने घर के सामने 'लिटिल फूड पैंट्री' लगाई ताकि जरूरतमंद पड़ोसियों को खाना मिल सके। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन के कारण अक्तूबर के बाद एसएनएपी फंडिंग रोकने का निर्णय लिया था, जिससे देशभर में मुकदमे शुरू हो गए। कुछ अदालतों ने सरकार को कम से कम आंशिक भुगतान करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने 65प्रतिशत तक लाभ देने की बात मानी।

ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन-झड़प, जानें क्यों नाराज हैं आदिवासी समुदाय

बेलेम, एजेंसी। ब्राजील के अमेजन शहर बेलेम में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन (कॉप30) के मुख्य स्थल पर मंगलवार को कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान दो सुरक्षाकर्मियों को मामूली चोटें आईं।

ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा टीम ने की कार्रवाई : मामले में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संगठन ने एक बयान में कहा, 'आज शाम, कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बैरियर तोड़ दिए, जिससे दो सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोटें आईं और स्थल को मामूली नुकसान हुआ। ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा टीम ने तय प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत कार्रवाई की। फिलहाल स्थल पूरी तरह सुरक्षित है और सम्मेलन की बातचीत सामान्य रूप से जारी है।

झड़प से पहले क्या हुआ था : घटना उस समय हुई जब दिन का सत्र समाप्त हो रहा था और लोग सम्मेलन स्थल से बाहर निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग पीली टी-शर्ट में थे, जबकि कुछ आदिवासी समुदाय के पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे। ग्लोबल यूथ गठबंधन के युवा समन्वयक आगस्टिन ओकाना, जो मौके पर मौजूद थे, ने बताया कि प्रदर्शनकारी शुरू में नाच-गाकर नारे लगा रहे थे। वह भी उनके साथ चलने लगे क्योंकि उनके कुछ दोस्त आदिवासी समूह में थे। ओकाना के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं था कि पहले किसने सुरक्षा घेरा तोड़ा, लेकिन जैसे ही गार्डों ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की और अतिरिक्त सुरक्षा बुला ली, स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 'वे हमारे बिना हमारे लिए फैसले नहीं कर सकते' के नारे लगा रहे थे। यह नारा इस बात का प्रतीक था कि आदिवासी समुदाय महसूस करते हैं कि जलवायु वार्ताओं में उनकी भागीदारी को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मौके पर मची अफरातफरी : जब टकराव बढ़ा, तो दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने पास रखे छोटे प्लास्टिक के बक्सों से एक-दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ओकाना ने बताया कि एक सुरक्षा कर्मी के सिर में चोट लगी और दो-तीन लोगों के शरीर पर चोट के निशान थे।

आदिवासी समुदायों की नाराजगी क्यों? : ओकाना ने कहा कि कई आदिवासी समुदाय नाराज हैं क्योंकि सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जलवायु सम्मेलन के लिए 'एक नया शहर खड़ा करने' में भारी धन लगा रही हैं, जबकि उनके क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जंगलों की सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें अब भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा, 'ये लोग बुरे नहीं हैं। वे हताश हैं, अपनी जमीन और नदी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।' ओकाना ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया जलवायु संरक्षण पर सिर्फ बातें करती रही और ठोस कदम नहीं उठाए, तो इस तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'यह घटना बस एक छोटी झलक है, अगर हमने धरती को बचाने की बातों को यूं ही टालते रहे, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौर्या (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली धमाका: मुख्य आरोपी डॉ. उमर कार में था मौजूद डीएनए में हुआ खुलासा

नई दिल्ली

दिल्ली लाल किला धमाके के मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी का डीएनए मैच हो गया है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा था। ये सभी सैंपल उमर की मां के डीएनए से मैच हो गए हैं। इधर, देर रात ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटवी फुटेज सामने आया है। 10 सेकेंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं।

शाम करीब 6.51 बजे सिग्नल ग्रीन हुआ, जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ीं, आई20 कार में धमाका हो गया। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठीं। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं, बल्कि दो कारें थीं। बुधवार को इसकी तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस गाड़ी की खबर सामने आई।

इस गाड़ी की जांच के लिए एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है। गाड़ी अभी तक पूरी तरह से खोली नहीं गई है। सूत्रों के अनुसार गाड़ी जहां मिली, वह उमर के ड्राइवर की बहन का घर था। वहीं, दिल्ली धमाके में पुलिस को एक लाल ईको स्पोर्ट्स कार के शामिल होने की भी जानकारी मिली।

करीब 10 घंटे जांच के बाद यह कार (डीएल10-सीके-0458) हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस मिली।कार का रजिस्ट्रेशन ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी के नाम पर है। फिलहाल फोरेंसिक और एनएसजी टीमें कार की जांच कर रही हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें संदेह है कि ये रेकी 26 जनवरी को ऐतिहासिक स्मारक को निशाना बनाने की एक बड़ी

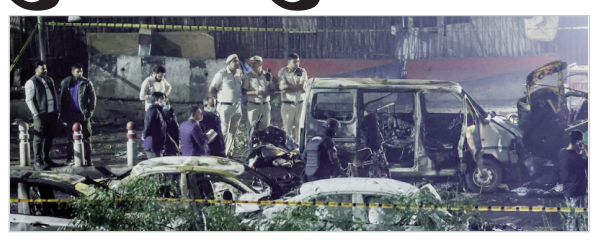

साजिश का हिस्सा थी, जो उस समय क्षेत्र में गहन गश्त के कारण विफल हो गई होगी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान खुलासा हुआ कि दो प्रमुख संदिग्ध, धमाके वाली आई-20 कार चला रहे डॉ. उमर और मुजम्मिल तुर्किये गए थे। उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं को उनके पासपोर्ट में तुर्किये के आव्रजन टिकट मिले हैं और वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या दोनों अपनी यात्रा के दौरान किसी विदेशी आका से भी मिले थे।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया, विमान हादसे में प्रारंभिक रिपार्ट में पायलट दोषी नहीं

नई दिल्ली

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पायलट को दोषी नहीं ठहराया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, डीजीसीए और अन्य अधिकारियों को एयर इंडिया बोइंग के पायलट-इन-कमांड दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था।

यह विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस घटना में 260 लोग मारे गए थे। याचिका में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जाँच की माँग की गई है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को भरोसा देकर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह दुर्घटना हुई, लेकिन आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी माना जा रहा है... कोई भी आपके सुपुत्र को दोषी नहीं ठहरा सकता। न्यायमूर्ति कांत ने स्पष्ट किया, भारत में कोई नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि प्रारंभिक एएआईबी रिपोर्ट में पायलट की ओर से किसी भी तरह की गलती का संकेत नहीं मिला है।

12 जून, 2025 को, एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 241 यात्रियों सहित 260 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के ईंधन इंजन के स्विच उड़ान भरने के बाद लगभग एक साथ रन से कटऑफ पर स्विच हो गए। अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट की आवाज की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कैप्टन सभरवाल ने इंजनों में ईंधन का प्रवाह बंद किया था।

मुंबई में अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश, अमेरिका-कनाडा के लोगों को ठगा

5 आरोपी गिरफ्तार, 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 76,000 नगदी बरामद

मुंबई

मुंबई की मुलुंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। मुलुंड पश्चिम के एक आवासीय फ्लैट में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी बरामद की है। मुलुंड पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिली थी कि मुलुंड कॉलोनी क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं। वे खुद को अमेरिका स्थित बैंक या वित्तीय कंपनी का अधिकारी बताकर विदेशी नागरिकों को तुरंत ऋण देने का लालच देते हैं। पीड़ितों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते हैं, लेकिन ऋण कभी नहीं देते। पुलिस ने जब फ्लैट पर छापा मारा तो वहां सागर गुप्ता मुख्य संचालक निकला। सागर ने इस धंधे के लिए अभिषेक सिंह, तन्मय धाड़ सिंह, शैलेश शेट्टी और रोहन को नियुक्त किया था। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 2 राउटर और 76,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कॉल सेंटर में खुद को लेंडिंग पॉइंट नामक वित्तीय कंपनी का कर्मचारी बताते थे। वे ई-सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पीड़ितों से

संपर्क करते थे। शिकार को असुरक्षित वेतन-दिवस ऋण देने का वादा करते थे। न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के बाद भी पीड़ितों को कुछ नहीं मिलता। इस तरह से लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के यह अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे।

सरकार की 10 लाख करोड़ के पेंशन फंड पर नजर

पेंशनधारकों में चिंता बढ़ी

नई दिल्ली

केंद्र सरकार देश के सबसे बड़े वित्तीय कोषों में से एक 10 लाख करोड़ रुपये के पेंशन फंड को लेकर नई योजना पर विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विशाल राशि को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सार्वजनिक निवेश और दीर्घकालिक विकास योजनाओं में लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार के इस कदम को लेकर पेंशनधारकों और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच चिंता और बहस देखने को मिल रही है।

वर्तमान में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत यह कोष मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड और कम जोखिम वाले साधनों में निवेश किया जाता है। सरकार अब इस फंड को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के रूप में उपयोग करने के बारे में सोच रही है। सरकार के अधिकारियों का मानना है, पेंशन फंड का जमा पैसा सड़कों, बिजली और रेलवे जैसी परियोजनाओं में लगाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इससे लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जमा फंड पर रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों की सरकार की इस सोच वाले प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति है। उनका कहना है, पेंशन फंड कर्मचारियों की जीवनभर की मेहनत की कमाई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और स्थिर रिटर्न देना है। नाकि पेंशन के लिए जमा

पूंजी को जोखिम भरे निवेश में लगाना। ट्रेड यूनियनों ने सरकार को चेतावनी दी है। अगर सरकार ने इस राशि को बाजार या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डाला। पेंशन कोष मे नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा।

दिल्ली विस्फोट.....500 जगहों पर रेड मारकर 600 लोगों को लिया हिरासत में

नई दिल्ली

दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद एजेंसियां हरकत में हैं। धमाके का कनेक्शन जम्मू-कश्मीर से जुड़ा है, वहां तक एजेंसियां अब संदिग्धों की तलाश में हैं। धमाके के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 500 जगहों पर रेड मारकर 600 लोगों को हिरासत में लिया है।

यह छापेमारी जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ हुई है। एजेंसियों का कहना है कि हमें इनपुट मिला था कि जमात-ए-इस्लामी फिर से खुद को जम्मू-कश्मीर में खड़ा करने की तैयारी में है। इसके बाद ही एक्शन हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बारामूला सहित कई जिलों में छापेमारी की गई है।

इस बीच सुरक्ष एजेंसियां डॉक्टर मॉड्यूल पर भी एक्शन ले रही है। तीन सरकारी कर्मचारियों सहित करीब 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जांच

अधिकारियों ने बताया कि रात भर की छापेमारी के दौरान अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों से संदिग्धों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों से पूछताछ में पता चला है कि उनमें से कुछ पिछले एक साल में तुर्किये भी गए थे। विस्फोटकों के भारी जखीरे की बरामदगी के सिलसिले में डॉक्टरों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांचकर्ताओं ने अब तक 'सफेदपोश आतंकी' मॉड्यूल के सिलसिले में 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। इस मॉड्यूल का खुलासा आतंकवादियों के दो गुर्गों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया गया, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में ही 200 ठिकानों पर और श्रीनगर में 150 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

ब्लैक फंगस के बाद अपनी मुस्कान गंवा चुके मरीजों के चेहरे पर फिर लौटी खुशी

भोपाल

ब्लैक फंगस (म्यूकोरमायकोसिस) के संक्रमण कई मरीजों का जबड़ा छीन लिया, मगर एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने इसतरह के कुछ मरीजों को फिर से मुस्कुराने का कारण दिया। कोरोना काल के बाद बीमारी से जबड़ा गंवा चुके 52 लोग अब न सिर्फ सामान्य जीवन जी रहे हैं, बल्कि आत्मविश्वास से समाज में सक्रिय हैं। सालभर घरों में कैद रहने वाले इन मरीजों को एम्स की सर्जरी टीम ने 'जायगोमैटिक इम्प्लांट' तकनीक से नया चेहरा और नई उम्मीद दी है।

इस शोध का नेतृत्व डॉ.अंशुल राय, प्रोफेसर (डेंटिस्ट्री विभाग) ने किया। उन्होंने बताया कि उद्देश्य सिर्फ सर्जरी नहीं, बल्कि मरीजों की जीवनशैली को सामान्य करना

था। ब्लैक फंगस के बाद जबड़ा गंवाने वाले अधिकांश मरीज समाज से कटे थे। वे अपने ही घर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते थे और हर वक्त चेहरा ढककर रहते थे। उनमें हीन भावना घर कर गई थी। इसके बाद एम्स की टीम ने उनके उपचार का बीड़ा उठाया और थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक से सटीक योजना बनाकर आंख के पास की हड्डी (जायगोमैटिक बोन) में 77 इम्प्लांट्स लगाए। यह बेहद जटिल सर्जरी थी, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सफल सर्जरी के बाद अब ये मरीज सामान्य रूप से बोल रहे हैं, खा-पी रहे हैं और आत्मविश्वास से समाज में शामिल हो रहे हैं।

जो चेहरे पहले नकाब के पीछे छिपे थे, अब वे खुले दिल से मुस्कुरा रहे हैं। एम्स भोपाल अब उन लोगों के लिए नई उम्मीद बन गया है, जो ब्लैक फंगस या गंभीर मुख-विकृतियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों की यह उपलब्धि न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र की सफलता है, बल्कि उन लोगों के लिए जीवन की नई शुरुआत है जिन्होंने कभी मुस्कुराना छोड़ दिया था।

लैंगिक समानता पर सफलता तब मिलेगी, जब महिलाएँ और पुरुष दोनों मिलकर सहयोग करें

सीजेआई जस्टिस गवई ने 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्या में कहा

नई दिल्ली

देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई ने लोगों से आह्वान किया है कि लैंगिक समानता की दिशा में हमारी यात्रा तभी सफल होगी, जब महिलाएँ और पुरुष दोनों मिलकर सहयोग कर और किसी भी चुनौती को पार पाने में पूर्ण सहयोग दें। इसके साथ ही सीजेआई गवई ने जोर देकर कहा कि लैंगिक न्याय हासिल करना सिर्फ महिलाओं की इकलौती जिम्मेदारी नहीं है।

सीजेआई गवई ने 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्या में ये बात कहीं। उन्होंने कहा, लैंगिक न्याय प्राप्त करना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए है। इसके लिए पुरुषों द्वारा, विशेष रूप से हमारे संस्थानों, कार्यस्थलों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता के पदों पर बैठे पुरुषों द्वारा, सत्ता की सक्रिय पुनर्कल्पना की जरूरत है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई गवई ने अपने व्याख्यान में 1950 में भारत के संविधान के लागू होने से लेकर 25-25 वर्षों के तीन चरणों में क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 1975 के बाद, लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय विमर्श औपचारिक अधिकारों के प्रश्नों से आगे बढ़कर, समानता के एक अभिन्न अंग के रूप में गरिमा के गहन विचार की ओर मुड़ने लगा। बातचीत केवल कानूनी समानता से आगे बढ़कर महिलाओं की स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और उनके जीवन के अनुभवों को आकार देने वाली सामाजिक वास्तविकताओं की मान्यता की ओर मुड़ गई।

उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की सतर्कता, महिला आंदोलनों की दृढ़ता और लोगों के साहस ने मिलकर न्यायपालिका को समानता के संवैधानिक वादे के प्रति जवाबदेह बना दिया है। सीजेआई गवई ने कहा कि मान्यता और समानता के लिए प्रारंभिक संघर्षों से लेकर अंतर्संबंधी और सहभागी न्याय के वर्तमान युग तक, अदालतें अक्सर समानता और मानव गरिमा के संरक्षक के रूप में खड़ी रही हैं।

जस्टिस गवई ने कहा, ''यह विकासक्रम चुनौतियों से रहित नहीं रहा है।

इसतरह के कई मौके आए जब न्यायिक व्याख्याएं महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों को सही तरह नहीं समझ सकीं या संविधान की परिवर्तनकारी भावना पर खरी नहीं उतरीं।

रोहतास जिले में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राजद का हंगामा.....डीएम ने किया खंडन

पटना

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा रोहतास जिले में ईवीएम (ईवीएम) को मतगणना केंद्र के अंदर घुसपैठ से ले जाने के आरोप और जिलाधिकारी द्वारा इसका खड़न किया गया है। राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तकिया बाजार समिति परिसर स्थित वज्र गृह मतगणना केंद्र के अंदर ले जा रहा था। इस आरोप के बाद, बुधवार देर रात राजद कार्यकर्ता और समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए एकत्र हुए। इसके बाद रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने राजद के दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ट्रक में खाली स्टील के बक्से थे, न कि ईवीएम मशीन थी। डीएम ने बताया कि उन्हें सूचना मिलने के बाद, उन्होंने जाँच में पाया कि ट्रक शाम 7:59 बजे बाज़ार समिति में घुसा था और उसकी प्रविष्टि लॉगबुक में दर्ज थी, जिसमें लिखा था कि ट्रक खाली बक्सों से भरा था। ट्रक की जाँच मौजूद सभी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की मौजूदगी में की गई। हर बक्सा निकाला गया और सभी बक्से खाली पाए गए। जाँच के बाद, सभी बक्सों को वापस ट्रक में लोड कर दिया गया। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले सभी से अफ़वाहें न फैलाने का आग्रह किया। रोहतास के एसपी रौशन कुमार ने बताया कि सुरक्षा के 3 स्तर हैं, जिसमें पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) शामिल हैं।

संक्षिप्त समाचार

कम उम्र के 65 बच्चों की कुपोषण से मौत.....बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा

मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के मेलघाट क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण के गंभीर संकट को उजागर करती हैं। महाराष्ट्र का आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र (अमरावती ज़िला)। जून और नवंबर 2025 के बीच, छह महीने से कम उम्र के 65 बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट (न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ) ने इसे भयावह बताते हुए राज्य सरकार की प्रतिक्रिया को बेहद लापरवाह और असंवेदनशील कहा है। अदालत ने ज़िक्र किया कि सरकारी विभागों को 2006 से इस मुद्दे पर आदेश मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हालात में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने जोर दिया कि यह आँकड़ों का नहीं बल्कि मानवीय अस्तित्व और करुणा का मामला है, जो जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। अदालत ने लोक स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल कल्याण और वित्त विभागों के प्रमुख सचिवों को 24 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह दर्शाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य सरकार के प्रयासों की कमी को लेकर न्यायपालिका कितनी चिंतित है।

दिल्ली धमाका, देश में अशांति फैलाने की यह एक घृणित साजिश: शाही इमाम

नई दिल्ली दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले की शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जाहिर करते कहा कि देश में अशांति फैलाने की यह एक घृणित साजिश है जिसे समाज के हर तबके को मिलकर नाकाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों, एकजुट होकर इस तरह की हिंसक घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इमाम ने कहा कि देश के मुसलमान भारतीय हैं और कश्मीरियों, सिख भाइयों तथा अन्य समुदायों के साथ मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो इसपर और इंसाफ होता हुए भी दिखे। उन्होंने कहा कि घटना से देश में भय फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा और अमन बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा। शाही इमाम ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि आतंकवादी हमले की पूरी तरह से जांच कराएं और इसके पीछे मौजूद अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।

यूपी और गुजरात एटीएस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, बड़ी जनहानि को रोका

लखनऊ और दिल्ली के मंदिरों और आरएसएस कार्यालयों की ली थी टोह

नई दिल्ली यूपी और गुजरात एटीएस ने 9 नवंबर को गुजरात में तीन लोगों को गिरफ्तार कर एक संदिग्ध आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की टीमें गुजरात भेजी गई थीं। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि आरोपी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जनहानि करने के लिए प्रसाद में घातक जहर रिसिन तैयार कर रहे थे। आरोपियों ने संभावित लक्ष्यों के रूप में लखनऊ और दिल्ली के मंदिरों और आरएसएस कार्यालयों की टोह ली थी। आजाद और सुहैल को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया गया और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उन्हें वीडियो प्रशिक्षण दिया गया। सूत्रों ने बताया कि संदिग्धों से बरामद गैजेट्स में यूपी के साथ-साथ दिल्ली और अहमदाबाद के स्थानों के वीडियो भी थे। यूपी एटीएस अब मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जांच से पता चला है कि आज़ाद और सुहैल को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मिले थे और वे आईएसकेपी से जुड़े एक अफगानिस्तान-स्थित हैंडलर के निर्देशन में काम कर रहे थे।